



सब का सपना



तीजोत्सव में महिलाओं ने बिखरे संस्कृति और उमंग के रंग				पेज: 4		निष्पक्ष व निडर - हिंदी दैनिक समाचार पत्र		मेरे करियर के हर पड़ाव पर पति करण बड़ा सपोर्ट बनकर सामने		पेज: 8	
वर्ष : 02	अंक : 138	शनिवार 22 अगस्त 2026	अमरोहा (उत्तर प्रदेश)	www.sabkasapna.com		पृष्ठ : 08	मूल्य: 2 रुपए				

माता–पिता पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे :रोहिणी आचार्य

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। केंद्रीय मंत्री जीवन राम मांडी को जवाब देने के बाद अब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से अपने रुख को स्पष्ट किया है। रोहिणी ने साफ कहा है कि उनके माता–पिता, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी, पर यदि कोई अभद्र या अमर्यादित टिप्पणी करना तो वह उसका जवाब उसी भाषा में देंगी। रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा कि उनके लिए माता–पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि माता–पिता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी होने पर उनकी ओर से जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा, जिस भाषा में टिप्पणी की गई होगी। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में केंद्रीय मंत्री जीवन राम मांडी का भी विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मांडी ने किसी अन्य व्यक्ति के बयान के संघर्ष में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बारे में टिप्पणी की थी, जबकि उस बयान से उनके माता–पिता का कोई लेना–देना नहीं था। रोहिणी के अनुसार, मांडी ने विषय से हटकर लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पर टिप्पणी की, जिसे उन्होंने पूर्वाग्रह से ग्रसित और ओछी टिप्पणी बताया। रोहिणी ने कहा कि एक बेटी होने के नाते ऐसी टिप्पणी का जवाब देना उनके लिए स्वाभाविक था। अपनी भाषा की मर्यादा पर बात करते हुए रोहिणी ने कहा कि वह इसका बखूबी ख्याल रखना जानती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग अपनी बात मर्यादा के दायरे में रखते हैं, वह उनकी मर्यादा का भी सम्मान करती हैं। उन्होंने उन मीडिया रिपोर्टों का भी जिक्र किया, जिनमें उनके किसी व्यक्ति के बचाव में खड़े होने या किसी का बचाव करने की बात कही जा रही थी। इस तरह के नरटिव को सिर से खारिज करते हुए रोहिणी ने कहा कि वह पल–पल अपनी राय बदलने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो उनके अनुसार गलत था या है, वह गलत ही रहेगा, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। उन्होंने कहा कि वह अपने स्टैंड, राय और विचार पर दृढ़ता से कायम रहने वालों में से हैं और आगे भी इसी तरह अपने विचारों पर कायम रहेंगी। रोहिणी के इस पोस्ट को हालिया राजनीतिक बयानबाजी के बीच उनके रुख को और अधिक स्पष्ट करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

राहुल गांधी के छात्रों की गुंज कार्यक्रम पर मचा सियासी घमासान, फडणवीस और सपकाल आमने–सामने

मुंबई (एजेंसी)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के पुणे दौरे से पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के वरिष्ठ नेता रविवर्धन सपकाल और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राहुल गांधी के छात्रों की गुंज कार्यक्रम को लेकर आमने–सामने आ गए हैं। फडणवीस ने दावा किया था कि राहुल गांधी का यह कार्यक्रम केवल कांग्रेस नेताओं द्वारा संचालित कॉलेजों के छात्रों तक ही सीमित रहेगा, जबकि सपकाल ने इसे सिर से खारिज कर दिया है। सपकाल ने स्पष्ट किया कि 22 अगस्त को एआईएसएसएमएस कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम सभी छात्रों के लिए खुला रहेगा। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पुणे पहुंचे सपकाल ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि यह छात्राओं के साथ सीधा संवाद का कार्यक्रम होगा। उन्होंने पुणे के ऐतिहासिक महत्व पर जोर देते हुए कहा, यह कार्यक्रम पुणे में हो रहा है, जो लड़कियों की शिक्षा की नींव रखने वाली सावित्रीबाई फुले और जीजामाता की भूमि है, जिन्होंने अपने पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदवी स्वराज्य का मंत्र दिया। फडणवीस ने नागपुर में बयान देते हुए कहा था कि उनकी जानकारी के अनुसार, गांधी कांग्रेस नेताओं द्वारा संचालित कॉलेजों में पंजीकृत छात्रों के साथ ही बातचीत करेंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम को एक नियंत्रित माहौल में होने वाला बताया और आशंका जताई थी कि यह खुले संवाद के बजाय एकतरफा भाषण हो सकता है। हालांकि, सपकाल ने फडणवीस के इस दावे पर कोई पाबंदी होने से साफ इनकार किया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। यह जुबानी जंग राहुल गांधी के पुणे में छात्रों के साथ सीधे जुड़ने के प्रयास से पहले राजनीतिक माहौल को गरमा रही है।

गुजरात में जहरीली शराब का कहर, मृतकों की संख्या 11, अस्पताल में 20 लोगों का इलाज

भावनगर (एजेंसी)। गुजरात के भावनगर जिले में जहरीली और नकली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। करीब 20 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। घटना के बाद भावनगर शहर और आसपास के इलाकों में अवैध शराब की बिक्री को लेकर प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नकली शराब को लोकप्रिय आईएमएफएल बांड की डुप्लीकेट बोतलों में भरकर बेचा गया। पुलिस के अनुसार, शराब की कुछ खेप मध्य प्रदेश से भावनगर पहुंची की आशंका है। मामले में पुलिस ने अब तक कई संदिग्ध शराब तस्करो को हिरासत में लिया है, बड़ी संख्या में नकली शराब की बोतलें जब्त की हैं। 21 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी है। गुजरात में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शहर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री के मामले सामने आने से पुलिस और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

युवाओं से संवाद बढ़ाएं और साइलो तोड़ें, पीएम मोदी ने दिए अधिकारियों को खास निर्देश

–तीसरी उच्चस्तरीय सचिव बैठक में दीर्घकालिक सोच, एआई–मानव समन्वय, डेटा साझाकरण और पोर्ट–लेड विकास पर दिया जोर

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के भविष्य के कार्य एजेंडे की समीक्षा की। बैठक में बुनियादी ढांचा एवं कनेक्टिविटी, सुरक्षा एवं विदेश मामलों तथा सुशासन से जुड़े विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों से विभागीय सीमाओं से ऊपर उठकर समन्वित कार्य संस्कृति विकसित करने और युवाओं के साथ सरकार का संवाद मजबूत बनाने का आह्वान किया। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों एवं विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बुधवार को हुई इस हाईलेवल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अधिकारियों को भी दीर्घकालिक सोच, एआई और नैतिकता के साथ सरकार का संवाद मजबूत बनाने का आह्वान किया।



क्रियान्वयन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में दूरदर्शी सोच अत्यंत आवश्यक है। विभागों के बीच तालमेल की कमी को 'साइलो' की समस्या बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक ढांचे की नहीं, बल्कि कार्यशैली और सोच की चुनौती भी है। उन्होंने अधिकारियों से अपनी जिम्मेदारियों का स्वाामित्व लेने तथा अपमान और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ काम करने को कहा।

कोविड-19 महामारी और पंथिम एशिया संकट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संकट के समय मंत्रालयों ने जिस प्रभावी समन्वय का प्रदर्शन किया था, उसे सरकार की स्थायी कार्य संस्कृति बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि एआई का अधिकतम उपयोग किया जाए, लेकिन मानवीय निर्णय क्षमता और विशेषज्ञता को उसके साथ जोड़े रखना आवश्यक है। इसी प्रकार उन्होंने डेटा को

देश की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति बताते हुए विभागों के बीच डेटा इंटरऑपरेबिलिटी और बेहतर साझाकरण की जरूरत रेखांकित की, ताकि उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग हो सके।

बैठक में विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और युवाओं के साथ सरकारी विभागों के संवाद को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी की भागीदारी से नीति निर्माण में नवाचार और अपरंपरागत विचारों को प्रोत्साहन मिलेगा। रक्षा अनुसंधान, जहाज निर्माण, पोर्ट–लेड डेवलपमेंट तथा विनिर्माण एवं नियात उद्योगों की बेहतर कनेक्टिविटी को लेकर भी उन्होंने मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों से कनिष्ठ अधिकारियों के साथ अधिक अनीपचारिक संवाद स्थापित करने, विभिन्न कैडरों और विभागों के बीच मजबूत नेटवर्क विकसित करने तथा पूरी सरकार में टीम भावना और समन्वित दृष्टिकोण को और सुदृढ़ बनाने का आग्रह किया।

जयपुर में भाजपा और सीजेपी कार्यकर्ताओं में टकराव, रांका को ग्रामीणों ने खदेड़ा

-सरकारी स्कूल का जायजा लेने पहुंचे ये सीजेपी कार्यकर्ता

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान की राजधानी जयपुर के गांव रामपुरा-कंवरपुरा में शुक्रवार को सरकारी स्कूल के निरीक्षण को लेकर भाजपा समर्थक ग्रामीणों और कार्यकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कार्यकर्ताओं के बीच खासा टकराव हो गया। दरअसल सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका अपनी टीम के साथ एक सरकारी स्कूल की असल स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने उनके स्कूल में प्रवेश का विरोध कर दिया। कहा-सुनी हुई और देखते ही देखते विवाद हाथापाई तक पहुंच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ग्रामीणों के विरोध के बाद रांका और उनके साथ आए कार्यकर्ताओं को मौके से लौटना पड़ा। रिपोर्टों में वाहनों के

शीशे टूटने और पथराव की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि, घटना को लेकर दोनों पक्षों के आरोप अलग-अलग हैं। रांका ने आरोप लगाया कि उनके साथियों के साथ मारपीट भाजपा समर्थकों ने की, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि वे गांव के सरकारी स्कूल में बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहते। मौजूदा विवाद की जड़ स्कूल भवन की खराब हालत बताई जा रही है। सीजेपी का दावा है कि बच्चे जर्जर भवन के कारण वैकल्पिक व्यवस्था में पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल भवन के लिए सरकारी बजट स्वीकृत हो चुका है और वे स्वयं इसके निर्माण को लेकर प्रयास कर रहे हैं। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस-प्रशासन का भूमिका पर भी नजर है।

बैठक में शामिल नहीं होने का आग्रह हाई कमान से किया था: चन्नी

सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल नहीं होने पर चन्नी ने दी सफाई

नई दिल्ली, एजेंसी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरुवार को खुलासा किया कि उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल न होने के लिए पार्टी आलाकमान से विशेष अनुरमति ली थी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में हुई इस उच्च-स्तरीय बैठक की जगह, उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय में अपनी परीक्षा में शामिल होना था, जिसे वे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे। चन्नी का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था सीडब्ल्यूसी की बैठक बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित की गई थी, जिसमें देश के ज्वलंत मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। एक पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में भी चन्नी का अकादमिक समर्पण उल्लेखनीय है। उन्होंने बताया कि यह उनके लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री की अंतिम परीक्षा थी, जिसे छोड़ना उनकी डिग्री में एक साल की देरी और उनके भावी शोध कार्यों को प्रभावित करता। चन्नी ने पहले ही पंजाब विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीएचडी की है और अब वे सार्वजनिक नीति में सुधार के क्षेत्र में आगे शोध करने में



भी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा, अगर मैं परीक्षा नहीं देता तो मेरी डिग्री में एक साल की देरी हो जाती और इस वजह से जिस शोधकार्य को मैं करना चाहता हूं, उसमें भी देरी हो जाती। उन्होंने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के बारे में कहा कि यह लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री की आखिरी परीक्षा थी और इसके बाद वे नीति सुधारों पर पीएचडी प्रोग्राम के लिए पंजाब विश्वविद्यालय से ही जुड़ेंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरेगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अन्य वरिष्ठ नेताओं और विशेष आमंत्रित सदस्यों के अलावा कांग्रेस-शासित राज्यों के सभी चार मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में हुई थी। इस लंबी बैठक में प्रश्नपत्र लोक के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन और अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की

चोरी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। बैठक के दौरान, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरेगे ने उत्तराखंड में अपने कार्यक्रम स्थल के शुद्धिकरण के मामले पर गहरा दुःख व्यक्त किया। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने पार्टी के कई सहयोगियों से समर्थन नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अच्छे लिखने और अच्छे दिखने वालों ने इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई। हालांकि, खरेगे ने इस घटना पर मजबूती से आवाज उठाने और भाजपा-आरएसएस को घेरने के लिए कांग्रेस की उत्तराखंड इकाई की सराहना की। कांग्रेस समिति की बैठक के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र के सी जे जे वेणुगोपाल ने बताया था कि सीडब्ल्यूसी ने खरेगे की सभा के स्थल के कथित शुद्धिकरण की घटना की कड़ी निंदा की है। वेणुगोपाल ने इस घटना को पूरी तरह अस्वीकार्य बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया और मांग की कि मोदी को इस संवेदनशील मुद्दे पर माफ़ी मांगनी चाहिए। यह घटना मल्लिकार्जुन खरेगे के उत्तराखंड दौरे के बाद उनके रैली स्थल को शुद्ध करने की थी, जिसे दलित अध्येक्ष के प्रति अपमानजनक और जातिवादी रवैये के रूप में देखा गया।

पानी समुद्र में बहे और किसान बूंद-बूंद को तरसे ये ठीक नहीं : शाह



- दो राज्यों के जल विवाद पर अमित शाह ने दी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंतरराज्यीय जल विवादों को बातचीत से सुलझाने के सुझाव को दक्षिण भारत के राज्यों ने समर्थन दिया है। गुरुवार को दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा, जहाँ लोकसभा सीटों के परिसीमन पर भी गहन चर्चा हुई। अमित शाह ने बैठक का अध्यक्षता करते हुए कहा कि अपने राज्य के हितों की रक्षा करना गलत नहीं

है, लेकिन अगर पानी की कमी के कारण किसी राज्य को वर्षों तक वंचित रहना पड़े और पानी समुद्र में बहता रहे, तो यह किसी के हित में नहीं है। शाह ने भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी से बचाने के लिए बढ़ापुत्र से कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने का सुझाव दिया, जिससे कई जलमार्ग भी विकसित हो सकते हैं। उन्होंने उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे के आठ में से पांच ब्रिटिश-पूर्व विवादों के सफल समाधान का उदाहरण दिया, जहां पांच महीने पहले अंतिम समझौता हुआ था।

हालांकि, बैठक में लोकसभा सीटों के परिसीमन का मुद्दा विवाद का विषय बन गया। दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण से उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व में नुकसान का आशंका जताई। कर्नाटक और तमिलनाडु ने मांग की कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें अगले 25 वर्षों तक बनीं रहें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने परिषद से प्रस्ताव पारित कर केंद्र से 1971 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाए रखने और महिलाओं के आरक्षण को मौजूदा सीटों के भीतर ही लागू करने की मांग की।

अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपनी चिंताओं के साथ सामने आए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु को मेकेंदातु बांध परियोजना से उनके हितों की रक्षा का आश्वासन दिया, हालांकि तमिलनाडु के मंत्री ने स्पष्ट किया कि कावेरी जल विवाद पर बैठक में चर्चा नहीं हुई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कुप्पम के रास्ते आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ने वाले बृहत् एन कॉरिडोर और अमरावती-बेंगलुरु-चेन्नई ट्रांजिट नेटवर्क का प्रस्ताव रखा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के बंटवारे

के मामलों को गृह मंत्रालय के साथ सुलझाने पर सहमत जताई। केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने मुख्यपेरियार बांध का मुद्दा उठाया और स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, परिवारण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा में सहकारी संघवाद पर जोर दिया। तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमरका ने कृष्णा नदी के पानी पर राज्य के अधिकारों की सुरक्षा और सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहयोग मांगा, जबकि पुडुचेरी ने सालमर पानी की उपलब्धता के लिए केंद्र और तमिलनाडु से सहयोग की अपील की।

सड़कों पर तड़तड़ाने लगी गोलियां और लहराने लगे हथियार, देहरादून में छात्र गुटों का खूनी तांडव

देहरादून (एजेंसी)। शिक्षा और शांति के लिए विख्यात देहरादून की पहचान को गुरुवार को छात्र गुटों के खूनी संघर्ष ने झकझोर दिया। पलनगर इंडस्ट्रियल एरिया से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते शहर की सबसे भीड़भाड़ वाली सड़कों पर करीब तीन किलोमीटर तक फैल गया, जिसमें पिस्टल और लाठी-डंडों का जमकर इस्तेमाल हुआ। दिनदहाड़े हुए इस तांडव में छह राउंड फायरिंग हुई और एक युवक घायल हो गया, जिससे शांत शहर में दहशत फैल गई। यह घटना देहरादून के बदलते मिजाज की एक खतरनाक तस्वीर पेश करती है, जिसे अब तक सुकुन और शिक्षा के केंद्र के तौर पर जाना जाता रहा है। सबसे गंभीर बात यह रही कि यह हिंसा किसी सुनसान कोने में नहीं, बल्कि शहर की मुख्य सड़कों पर हुई, जहाँ एक पक्ष कार में तो दूसरा बाइकों से पीछा कर रहा था। रास्ते में चार पुलिस पिंकेट होने के बावजूद यह विवाद एक स्थान पर नहीं रुका, बल्कि शहर के भीतर दौड़ता हुआ दूसरी जगह पहुंचा। यह सिर्फ एक आकस्मिक घटना नहीं है, यह उस गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है जब छात्र गुटों की रंजिश कैम्पस की सीमाओं को लांघकर सड़क पर उतर आती है और विवाद का जवाब तर्क से नहीं, बल्कि हथियारों से दिया जाता है। देहरादून में छात्र गुटों के बीच हिंसा का यह पहला मामला नहीं है। कुछ महीने पहले हुए वियाथ्रू जटरणा हत्याकांड ने भी छात्र विवादों के खूनी अंजाम की भयावहता दिखाई थी। उस घटना के बाद छात्र गतिविधियों पर निगरानी और संस्थानों के साथ समन्वय की बातें कही गई थीं, लेकिन गुरुवार की घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई का असर सिर्फ घटना के बाद ही दिखाई देता है। हजारों बाहरी छात्र देहरादून में किराये के मकानों और छात्रावासों में रहते हैं, लेकिन उनकी गतिविधियों पर पुलिस सत्यापन और निगरानी का तंत्र कमजोर दिखता है।

मंदिर निर्माण से जुड़ा कोई भी कार्य समिति के अध्यक्ष के फैसले के बिना नहीं हुआ

–पूर्व महासचिव चंपत राय ने नृपेंद्र मिश्र को लेकर नौ पत्रों का पत्र जारी कर लगाए आरोप

नई दिल्ली, एजेंसी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर विवाद एक बार फिर सामने आया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे नृपेंद्र मिश्र को लेकर नौ पत्रों का पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने मंदिर निर्माण से लेकर परिसर के विकास, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और ट्रस्ट की व्यवस्था तक कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। मांडिया रिपोर्ट के मुताबिक चंपत राय ने आरोप लगाया कि मंदिर निर्माण से जुड़े अहम फैसलों में नृपेंद्र मिश्र की भूमिका के बेहद प्रभावशाली रही और उनकी पसंद के लोगों को समिति में शामिल किया गया। चंपत राय के अनुसार, उन्होंने डिजाइन समिति की बैठकों में फैसले लिए जाते थे, लेकिन कई मामलों में बाद में बदलाव कर

नृपेंद्र मिश्र के निर्णयों को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने दावा किया कि मंदिर निर्माण से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण कार्य समिति के अध्यक्ष के फैसले के बिना नहीं हुआ। पत्र में यह भी कहा गया है कि उनकी पसंद के कुछ लोग समिति में शामिल किए गए, जिनमें से कुछ छह साल में केवल एक-दो बार ही अयोध्या आए हैं। चंपत राय ने कहा कि नृपेंद्र मिश्र के सुझाव पर लार्सन एंड टुब्रो को मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स को परियोजना प्रबंधन सलाहकार बनाया गया। मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा को 1986 में अशोक सिंघल ने चुना था और बाद में उन्हें ही निर्माण योजना में बनाए रखा। परिसर के अन्य भवनों के डिजाइन का काम नोएडा की डिजाइन एसोसिएट फर्म को दिया गया। चंपत राय ने पत्र में राम

जन्मभूमि विवाद के इतिहास और मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने तक की घटनाओं का भी उल्लेख किया। चंपत राय ने मंदिर की दर्शन व्यवस्था और वित्तीय प्रणाली की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद प्रतिदिन 75 हजार से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने लगे। महाकुंभ में यह संख्या तीन लाख से ज्यादा थी। श्रद्धालुओं के लिए आठ अलग-अलग लाइनें बनाई गई हैं। ट्रस्ट के बैंक खातों में चेकबुक का इस्तेमाल नहीं होता और भुगतान बैंक ट्रॉंसफर से किए जाते हैं। खातों का आंतरिक और वैधानिक ऑडिट भी कराया जाता है।



बता दें राम मंदिर में चढ़ावे चोरी का मामला सामने आने के बाद चंपत राय ने 26 जून को महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 6 जुलाई को उन्होंने ट्रस्टी अजित मिश्र को लेकर भी आरोप लगाए थे। अब नृपेंद्र मिश्र पर जारी नौ पत्रों के पत्र से मंदिर निर्माण और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर विवाद फिर चर्चा में आ गया है।

इथेनॉल नीति से महंगी हुई चीनी, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली, एजेंसी।



परिणामस्वरूप केवल पिछले तीन महीनों में चीनी की कीमतें 48 रुपये से बढ़कर 67 रुपये प्रति किलो हो गईं। गुडू भी 50 रुपये से 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है, जबकि चावल और मक्के के आटे में क्रमशः 16 और 11 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। पशु आहार के दाम भी 10.34 फीसदी बढ़े हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी सवाल उठाया कि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में कमी और इथेनॉल मिश्रण से लागत कम होने के बावजूद पेट्रोल के दामों में कोई कमी क्यों नहीं की गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी लगातार

अपनी चिंता व्यक्त की थी। कांग्रेस ने तत्काल इस नीति की समीक्षा करने और उपभोक्ताओं को बिना इथेनॉल वाले ईंधन का विकल्प उपलब्ध कराने की मांग की है, क्योंकि गाड़ी भी महंगी और रस्ती भी वाली ऐसी जर्नलियों ईंधन नीति देश को स्वीकार्य नहीं है। बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने 20 अगस्त को 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात को मंजूरी दी है, जो बीते एक दशक में ऐसा पहला मौका है। दिल्ली में 21 अगस्त को चीनी 65 रुपये प्रति किलो बिक रही है।

संपादकीय

हेल्थकेयर की चुनौतियां

यह विडंबना ही है कि देश में कभी भी सताधीशों की प्राथमिकता सरकारी चिकित्सा-तंत्र को सक्षम बनाने की नहीं रही है। किसी भी चुनाव में स्वास्थ्य सुविधाओं को समृद्ध बनाना राजनीतिक दलों के एजेंडे में शामिल नहीं रहा। जनता भी हर आम परिवार से जुड़े सेहत के मुद्दे को जोर-शोर से उठाने में चुकती रही है। यही वजह है कि आज भी कुल मिलाकर देश के करोड़ों लोगों के लिये सस्ती व पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच से बाहर हैं। अपने परिजनों के गंभीर रोगों के उपचार के लिये क्षमता से अधिक पैसा जुटाने के फेर में हजारों परिवार हर साल गरीबी की दलदल में धंस जाते हैं। यह गंभीर स्थिति सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में हेल्थकेयर पर बनी संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट साफ तौर पर दर्शाती है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के 2025 के सर्वे का हवाला देते हुए संसदीय समिति ने पाया है कि सरकारी सुविधाओं में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज का औसत खर्च 6,631 रुपये है, जबकि प्राइवेट में यह खर्च 50,508 रुपये है। निजी अस्पताल में होने वाला यह औसत खर्च सरकारी अस्पताल में होने वाले खर्च के मुकाबले सात गुना से भी अधिक है। जो चिकित्सा सुविधाओं में व्याप व्यापक विसंगतियों को ही दर्शाता है। यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है कि निजी अस्पताल अब साठ फीसदी से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती करते हैं और 70 फीसदी आउट पेशेंट की देखभाल करते हैं। विडंबना यह है कि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का अभाव लगातार बना रहता है। वहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी मरीज महसूस करते हैं। सरकारी अस्पताल की सुविधाओं में बेड, उपकरण, दवाइयां और कुशल स्टाफ की कमी देखी जाती है। मरीज को भरोसा नहीं होता है कि उसे जरूरी इलाज सरकारी अस्पताल में मिल भी पायेगा। एक संकट यह भी है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों का दबाव बहुत ज्यादा होता है। उसके मुकाबले चिकित्सक उपलब्ध नहीं होते हैं। वहीं दूसरी ओर निजी अस्पतालों में चिकित्सकों की अच्छी आय और निजी प्रिवेटस का सम्मोहन भी योग्य डाक्टरों को सरकारी अस्पतालों से विमुख बनाता है। यही वजह है कि पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में मरीजों को निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिये बाध्य होना पड़ता है। दरअसल, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता, अब चाहे उनकी पैसा देने की क्षमता हो या न हो। लोगों की चिकित्सा इमरजेंसी की चिंता की वजह से स्वास्थ्य बीमा का बड़ा कारोबार देश में फल-फूल रहा है।

चिंतन-मनन

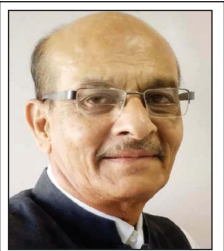
चैन से सोना है तो सोने को कर्हें ना

सोने की चमक सभी को आकर्षित करती है। इसी आकर्षण के कारण लोग अधिक से अधिक सोना खरीदने चाहते हैं। यह चाहत तब और भी बढ़ जाती है जब सोने की कीमत में अचानक थोड़ी गिरावट आती है। लोग इस मौका का लाभ उठाना चाहते हैं। आज कल बाजार में यही स्थिति है क्योंकि सोने की कीमत कमी आयी है। आइए जॉन से सोने के बारे में हमारे शास्त्रों क्या कहा गया है। ज्यादातर पौराणिक ग्रंथों में इस बात को कई तरह से कहा गया है कि सोने की खरीदारी से जितनी खुशी नहीं होती है उससे अधिक चिंता बढ़ जाती है। हमेशा यह चिंता साताती है कि सोना चोरी न हो जाए। इसे कैसा सभालकर रखें। पड़ोसी की नजर सोने के गहनों पर नहीं जाए, क्योंकि नजर लग जाएगी।यह भी कहा जाता है कि किसी अवसर पर सोने के गहने पहन लें तो हमेशा इसी पर ध्यान रहता है कि कहीं गिर न जाए, कोई खींच न ले। इस चिंता के कारण उत्सव का पूरा आनंद भी नहीं उठा पाते हैं। सोना सिर्फ आपको चिंतित ही नहीं करता है बल्कि आपकी सोच और व्यवहार को भी प्रभावित करता है। इससे अधिमान भी जन्म लेता है। यही कारण है कि रहीम ने लिखा है कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय। वा खाये बौराय नर, वा पाये बौराय।। इस दोहे में रहीम ने दो बार कनक शब्द का प्रयोग किया है। एक कनक धतूरे के लिए और दूसरा सोना के लिए। रहीम ने कहा है कि सोने का नशा धतूरे भी ज्यादा होता है। धतूरा खाने के बाद आदमी बौरा जाता है लेकिन सोने का नशा इतना तेज होता है कि इसे प्राप्त कर लेने मात्र से इंसान बौरा जाता है। पुराणों में कथा है कि कलियुग का प्रवेश भी सोने के माध्यम से हुआ था। कलियुग सोने में निवास करता है इसलिए सोने के कारण विवाद और रिस्तों में दूरियां तक आ जाती है। साधु पुरुष कहते हैं कि सोना चिंता का बड़ा कारण है। जब आप इसे पाने की सोचने लगते

आवश्यकता है

आवश्यकता है दैनिक सब का सपना समाचार पत्र को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर व जिला स्तर पर संवाददाताओं की इच्छुक अभ्यर्थी संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।

9456884327/8218179552



सनत जैन

जयपुर के रामपुरा-कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल की स्थिति देखने पहुंचे कॉंकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों की झड़प और मारपीट की घटना ने शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सीजेपी का आरोप है, इस विरोध के पीछे भाजपा समर्थक थे। उपलब्ध रिपोर्ट में भाजपा ने दावा किया है, ग्रामीणों ने कॉंकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध करते हुए उनके साथ मारपीट कर उनके वाहनों को नुकसान पहुंचाया है। इसमें भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है। मुद्दा केवल यह नहीं है, जयपुर में किसने किसे पीटा। असली प्रश्न यह है, सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति देखने, उसकी तस्वीर लेने और उसे जनता के सामने रखने से किसे डर लग रहा है? राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश तथा फोटो-वीडियोग्राफी के लिए प्रधानाचार्य की अनुमति अनिवार्य करने का आदेश क्यों सामने आया है? छात्रों से बातचीत करने पर क्यों रोक लगाई जा रही है? आदेश पर सरकार का तर्क बच्चों की सुरक्षा, निजता और विद्यालय में अनावश्यक व्यवधान को रोकने की बात कही जा रही है। यह तर्क पूरी तरह से सही नहीं है। यह आदेश ऐसे समय पर आया है जब जेन-अल्फा के स्कूली छात्र-छात्राएं अपनी मांग को लेकर कई राज्यों के कई स्थानों

स्कूलों के दरवाजे बंद, सवालों से क्यों डर रहीं हैं सरकारें?

पर सड़क पर उतरे हैं। जब सीजेपी एवं अन्य राजनीतिक दल सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर अभियान चला रहे हैं, तब स्वाभाविक रूप से पारदर्शिता और सच को छुपाने को लेकर सवाल उठते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बिना अनुमति सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों और यूट्यूबर्स के प्रवेश पर रोक की खबर है। वहां भी प्रशासन का तर्क सुरक्षा और पढ़ाई में व्यवधान बताया गया है। यह कहना कि दोनों राज्यों में भाजपा की सरकारें अपनी कमियां छिपाना चाहती हैं। पारदर्शिता और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, यह सवाल जरूर महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े छात्र संगठनों की सक्रियता को इसी व्यापक राजनीति से जोड़ा जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भाजपा से जुड़े हुए अनुवांशिक संगठन लंबे समय से विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश कर-के वहां हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन पर इस तरीके की कोई रोक-टोक नहीं है। यदि कोई संगठन स्कूल-कॉलेजों की समस्याओं को देखकर और सुनकर समाधान के लिए प्रशासन और सरकार के सामने लाना चाहते हैं, तो लोकतंत्र में उसका स्वागत होना चाहिए। यही अधिकार विपक्षी दलों और स्वतंत्र सामाजिक संगठनों को भी मिलना चाहिए। इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। शिक्षा संस्थान किसी राजनीतिक दल की जागीर नहीं हैं। वे जनता के पैसे से चलते हैं। वहां पढ़ने वाले बच्चे समाज के भाग्य हैं। स्कूल की टूटी छत, जर्जर भवन, शिक्षक की कमी, शौचालय, पेयजल, प्रयोगशाला या पाठ्यपुस्तकों की कमी की किसी भी समस्या को उजागर करने वाला व्यक्ति राजनीतिक विरोधी हो सकता है। कम उम्र के छात्रों की समस्या को खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल है। ऐसी स्थिति

में कम उम्र के छात्रों के अधिकार को कैसे छीना जा सकता है। जयपुर की घटना इसलिए गंभीर है, क्योंकि सीजेपी शिक्षा एवं परीक्षा संबंधी मुद्दिम को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है। राजस्थान में प्रशासन, पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं से टकराव की खबरें सामने आना चिंता का कारण है। कुछ दिन पहले अलवर में जर्जर स्कूल को लेकर सीजेपी अभियान के बाद सरकार द्वारा मांगें स्वीकार किए जाने की रिपोर्ट आई थी। इसका अर्थ यह है कि दबाव बनाने वाली सक्रियता से व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। राजनीति का सबसे खतरनाक रूप तब सामने आता है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जंग मुद्दों पर नहीं, बल्कि एक-दूसरे को मैदान से हटाने के लिए होने लगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसी संगठन के कार्यकर्ताओं पर हमला किया है? तो वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। यदि सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश किया या स्थानीय लोगों को आपत्ति थी, उसके लिए कानून के तहत शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया होनी चाहिए। भीड़ को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सोशल मीडिया पर चल रहे जेन जेड और जेन अल्फा से जुड़े आंदोलनों को लेकर भी राजनीतिक दलों में नई रणनीतियां बनना शुरू कर दी हैं। छात्र एवं युवा अब आश्वासन राजनीतिक भाषण नहीं सुनता हैं। वह अपनी समस्याओं का समाधान निश्चित समय सीमा पर चाहता है। वह सवाल का जवाब भी तुरंत चाहता है। आने वाले समय में शिक्षा, रोजगार, परीक्षा व्यवस्था, फीस, डिजिटल अधिकार और सरकारी संस्थानों की पारदर्शिता बड़े राजनीतिक मुद्दे बनेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा और सच परिवार यदि युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सक्रियता बढ़ाते हैं। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विपक्षी दल भी ऐसा करने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष

और विपक्ष को समान अधिकार प्राप्त हैं। मुकाबला होना चाहिए,विचारों में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। सरकार के लिए सबसे अच्छा रास्ता स्कूलों के दरवाजे बंद करना नहीं, स्कूलों की समस्याओं को जवाबदेही के साथ सुलझाना और पारदर्शी बनाना है। कोई भी कैमरा वहां की व्यवस्था की सच्चाई को दिखाएगा, तो व्यवस्था से जुड़े हुए लोग जवाबदेह होंगे। सरकार को इसमें शर्मिंदा होने के स्थान पर, जिन अधिकारियों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी थी, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि व्यवस्थाओं में सुधार हो। बाहरी लोगों के प्रवेश के लिए नियम बनाना उचित हो सकता है, मगर स्वतंत्र निरीक्षण, पत्रकारिता और जनप्रतिनिधियों की निगरानी के लिए स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। जयपुर में जो घटना हुई है, उसकी निष्पक्ष जांच से सच सामने आना चाहिए। इसमें भाजपा कार्यकर्ताओं की भूमिका है, तो उन पर कार्रवाई हो, यदि किसी पक्ष ने कानून तोड़ा है, उसके खिलाफ समान कार्रवाई हो। लोकतंत्र में सत्ता की असली ताकत विरोधी आवाज को दबाने में नहीं, बल्कि विरोधी आवाज सुनकर व्यवस्था को बेहतर बनाने में है। सरकारी स्कूलों के दरवाजे बच्चों के लिए खुले रहने चाहिए। उनकी समस्याओं पर सवाल पूछने वालों के लिए भी लोकतांत्रिक रास्ते भी खुले रहने चाहिए। सवाल स्कूल का नहीं छात्रों के मौलिक अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। यदि 16 साल से कम उम्र के छात्र सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, यह सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण है। वर्तमान का बच्चा अपनी जरूरत के लिए इसी तरह का प्रदर्शन अपने घर पर भी करता है और अब वह स्कूल में उसकी जो जरूरत है उन मांगों को लेकर जब सड़कों पर उतर रहा है तो इस मामले को दबाया नहीं जा सकता है। बच्चे तो बच्चे हैं, ज़िद करेंगे, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी। उनका प्रदर्शन आक्रामक ही होता जाएगा।

सड़क पर पैदल चलना भी मौलिक अधिकार, फिर फुटपाथ क्यों बेहाल?

था, जिसमें पांच साल के एक बच्चे की सड़क पर टैकर की चपेट में आने से मौत हो गई थी। वहां न फुटपाथ था और न ही सड़क पार करने की सुरक्षित व्यवस्था। कहना गलत नहीं होगा कि आज कई भारतीय शहरों में फुटपाथ पर अतिक्रमण, टूटे या गायब फुटपाथ, सड़क पार करने के लिए अपर्याप्त क्रॉसिंग, तेज रफ्तार वाहन और यातायात नियमों का उल्लंघन पैदल यात्रियों के लिए जोखिम बढ़ाते हैं और हमारे देश में पैदल यात्रियों की सुरक्षा अभी भी एक गंभीर चुनौती है। आंकड़ों की बात करें तो सरकारी भारत में सड़क दुर्घटनाएँ-2023 के अनुसार, वर्ष 2023 में 35,221 पैदल यात्रियों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई, जो कुल सड़क दुर्घटना मौतों का 20.4% थी।सच तो यह है कि आज पर्याप्त पैदल यात्री बुनियादी ढाँचे का आवश्यकता है। यहां पाठकों को बताता चलूँ कि फुटपाथों का निर्माण और रखरखाव मुख्यतः राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के दायरे में आता है, इसलिए सरकारों और संबंधित निकायों को इन पर ध्यान देना चाहिए। यहां पाठकों को बताता चलूँ कि वैसे विश्व में सड़क की गुणवत्ता, फुटपाथ, पैदल पार-पथ, ट्रैफिक नियंत्रण और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के मामलों में नीदरलैंड को दुनिया के सबसे अच्छे उदाहरणों में गिना जाता है। सच तो यह है कि नीदरलैंड पैदल चलने के लिए दुनिया में एक अग्रणी देश है, जहां पैदल और साइकिल यात्रियों के लिए अलग एवं सुरक्षित मार्ग, कम गति वाले क्षेत्र और बेहतर सड़क डिजाइन

उपलब्ध हैं। नीदरलैंड के बाद डेनमार्क विशेषकर कोपेनहेगन में पैदल यात्रियों के लिए सुव्यवस्थित फुटपाथ, क्रॉसिंग और ट्रैफिक-शांत क्षेत्र हैं। वहीं पर स्वीडन विश्व में कम पैदल मृत्यु दर और मजबूत सड़क-सुरक्षा व्यवस्था के कारण अग्रणी देशों में शामिल है।नॉर्वे(यूरोप में) तथा फिनलैंड भी पैदल मार्गों और सड़क पार करने की सुरक्षित व्यवस्था के मामले में विश्व में अहम और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हाल फिलहाल, यहां यह कहना चाहूंगा कि 19 जून 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क पर पैदल चलने के संदर्भ में जो फैसला दिया है,इस फैसले का सीधा सा संदेश यही है कि सरकार और स्थानीय निकायों की यह जिम्मेदारी है कि ये लोगों को सुरक्षित फुटपाथ और सड़क पार करने की उचित सुविधा उपलब्ध करायें। वास्तव में सच तो यह है कि नगर निगम, नगरपालिका, शहरी विकास प्राधिकरण और पंचायतों को आगे आकर इस दिशा में गंभीरता और संवेदनशीलता से काम करना होगा।बहरहाल, यदि हम यहां पर आंकड़ों की बात करें तो, आंकड़े हमारी चिंताएं बढ़ाते हैं। यह बहुत ही दुःखद है कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में लगभग 20 प्रतिशत से अधिक लोग पैदल यात्री होते हैं। कई शहरों में फुटपाथ टूटे हुए, संकरे, असुरक्षित या लगातार बाधित पाए गए हैं। यानी समस्या केवल फुटपाथ बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित, चौड़ा, समतल और सभी के लिए सुगम बनाने की है। वास्तव



में,इसके लिए यह बहुत ही जरूरी है कि फुटपाथों पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग न हो, वहां पर पर्याप्त रोशनी हो, सड़क पार करने के लिए सुरक्षित क्रॉसिंग बने और दिव्यांगजनों के लिए रैप तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों। सड़क की खुदाई या निर्माण कार्य के दौरान भी पैदल यात्रियों के रास्ते को पूरी तरह बंद नहीं किया जाना चाहिए।

निष्कर्षतः यह बात कही जा सकती है कि सड़कें केवल वाहनों के लिए नहीं हैं। पैदल यात्री, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांगजन सभी सड़क के बराबर अधिकार रखते हैं। सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध कराना सुविधा नहीं, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकार और सरकार की जिम्मेदारी का हिस्सा है। (सुनील कुमार महला, प्रीलांस राइटर, कॉलिमिस्ट व युवा साहित्यकार।)

कब तक जारी रहेगा जहरीली शराब का जानलेवा कहर?



के पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ त्रासदी इलाकों में जहरीली शराब पीने से 14 से 18 लोगों की जान चली गई। पुलिस जांच के अनुसार, अवैध रूप से अधिक मुनाफा कमाने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रेड का घातक मेथेनॉल मिक्स किया गया था।आई माह में ही पंजाब के अमृतसर के पांच गांवों में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हुई थी। गुजरात ने जुलाई 2022 में भी भयावह शराब त्रासदी देखी थी। बोटार और आसपास के इलाकों में जहरीली शराब से 42 लोगों की मौत हुई थी और दर्जनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उस समय भी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, अधिकारियों का तबादला हुआ और अवैध शराब के नेटवर्क को तोड़ने के दावे किए गए थे। सवाल है कि चार वर्ष बाद भी यदि नकली शराब लोगों तक पहुंच रही है तो पिछली कार्रवाई से हमने आखिर सीखा क्या? यह समस्या केवल गुजरात तक सीमित नहीं है। पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्य समय-समय पर ऐसी त्रासदियों के गवाह बने हैं। तमिलनाडु के कालाकुर्ची में जून 2024 में मेथेनॉल मिली अवैध शराब ने दर्जनों परिवारों को उजाड़ दिया था। आधिकारिक कार्रवाई के दौरान अवैध शराब जब्त हुई, गिरफ्तारियां हुईं और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में भी अवैध एवं नकली शराब के सेवन से होने वाली मौतों को अलग श्रेणी में दर्ज किया जाता है। उपलब्ध एनसीआरबी आधारित डेटा 2012 से 2024 तक राज्य वार ऐसी मौतों का हवाला देता है। इससे इतना तो साफ है कि यह किसी एक राज्य या एक क्षेत्र विशेष की समस्या नहीं, बल्कि दशकों से चली आ रही एक खतरनाक चुनौती है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि अक्सर इन घटनाओं में मरने वाले लोग समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल कमजोर

वर्ग से आते हैं। सस्ती शराब की तलाश उन्हें ऐसे अवैध कारोबारियों तक पहुंचा देती है जिन्हें न गुणवत्ता की चिंता होती है, न कानून का भय और न इंसानी जीवन की कीमत का पहसास। अधिक नशा पैदा करने या लागत कम रखने के लिए शराब में मेथेनॉल जैसे जहरीले रसायनों की मिलावट जानलेवा साबित हो सकती है। कल्लाकुर्ची मामले में भी मेथेनॉल मिश्रित शराब की पुष्टि सामने आई थी। अधिकतर देखा जाता है कि हर बड़ी आसदी के बाद प्रशासन की एक परिचित तस्वीर सामने आती है। छपेमारी शुरू होती है, अवैध टिकाने बंद किए जाते हैं, संदिग्ध गिरफ्तार होते हैं और पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा जाता है। लेकिन असली चुनौती घटना के बाद कार्रवाई करने की नहीं, घटना होने से पहले नेटवर्क को समाप्त करने की है। अवैध शराब का कारोबार अकेले किसी गली या गांव में बैठा व्यक्ति नहीं चला सकता। कच्चा माल कहां से आता है? बोटलें कहां बनती हैं? लोकप्रिय कंपनियों के नाम और लेबल की नकल कैसे होती है? माल एक जिले से दूसरे जिले और कई बार एक राज्य से दूसरे राज्य तक कैसे पहुंचता है? परिवहन, भंडारण और बिज्की की जानकारी स्थानीय स्तर पर किसी को क्यों नहीं मिलती? यदि वर्षों तक कारोबार चलता रहता है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही, स्थानीय संरक्षण या भ्रष्ट तंत्र भी इसका रास्ता आसान कर रहा है। शराबबंदी वाले राज्यों के लिए यह समस्या और बढ़ी चुनौती है। केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं होता। यदि वैध बिज्की बंद होने के बाद अवैध बाजार पैदा हो जाए और उसकी निगरानी कमजोर रहे तो त्स्करों को अधिक मुनाफे का अवसर मिलता है। शराबबंदी का उद्देश्य समाज को नशे से बचाना है, लेकिन यदि उसी व्यवस्था के भीतर जहरीली शराब का संगठित बाजार फलने लगे तो नीति की

समीक्षा और क्रियान्वयन दोनों जरूरी हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि शराबबंदी गलत है या शराब की खुली बिज्की समाधान है। असली प्रश्न नीति से अधिक उसके प्रभावी क्रियान्वयन का है। जहां प्रतिबंध है वहां अवैध सप्लाई पर कठोर निगरानी होनी चाहिए और जहां शराब की कानूनी बिज्की है वहां नकली उत्पादों की पहचान और वितरण व्यवस्था पर नियंत्रण मजबूत होना चाहिए। सरकारों को अब प्रत्येक त्रासदी के बाद केवल मुआवजा देने और कुछ लोगों को निलांबित करने से आगे बढ़ना होगा। अवैध शराब के मामलों में सप्लाई चेन की तह तक जांच, औद्योगिक मेथेनॉल की बिज्की और परिवहन की निगरानी, नकली ब्रांड और पैकेजिंग बनाने वालों पर कार्रवाई तथा बार-बार अवैध कारोबार में पकड़े जाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जरूरी है।यह सारा अवैध कारोबार बिना सरकारी तंत्र की मिलीभगत के सम्भव नहीं है स्थानीय पुलिस और आवकारी अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इसके साथ ही ग्रामीण और गरीब बस्तियों में जागरूकता बढ़ानी होगी। लोगों को बताया जाना चाहिए कि अनजान स्रोत से खरीदी गई शराब जानलेवा हो सकती है। संदिग्ध शराब पीने के बाद उल्टी, चक्कर, दृष्टि धुंधली होने वा अन्य परेशानी के मामलों में तुरंत अस्पताल पहुंचना बेहद जरूरी है। कई बार इलाज में देर भी मौतों की संख्या बढ़ा देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहरीली शराब से हुई हर मौत को महज एक आंकड़ा समझने की मानसिकता बदलनी होगी। मरने वाला किसी परिवार का कमाने वाला सदस्य, बेटा, पिता या भाई होता है। उसके जाने के बाद परिवार केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक संकट में भी डूब जाता है। देश में तकनीक बढ़ी है, पुलिस के पास आधुनिक संसाधन हैं, राज्यों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान पहले से आसान हुआ है। ऐसे में यह स्वीकार करना मुश्किल है कि अवैध शराब की पेटियां एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचे और व्यवस्था को भ्रमक तक न लें। भावनगर की घटना फिर चेतावनी दे रही है कि नकली शराब केवल कानून-व्यवस्था का सवाल नहीं, बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा का प्रश्न है। कार्रवाई तब सार्थक होगी जब आगली त्रासदी होने से पहले अपराधी नेटवर्क खत्म किया जाए। हर घटना के बाद वही सवाल पूछने की मजबूरी आखिर कब समाप्त होगी, कब थमेगा जहरीली शराब का कहर और कब बंद होगा बेगुनाहों की मौतों का यह सिलसिला। एक मौत पूरे परिवार को मार देती है कई बार परिवार के एक मात्र कमाने वाले सदस्य की मौत से पूरा परिवार प्रभावित होता है। सरकार को इन मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए।

कभी बेकार नहीं जाती और निरंतर प्रयास का परिणाम अवश्य मिलता है। पुलिस अधीक्षक ने यूपीएससी परीक्षा की प्रक्रिया के संबंध में विद्यार्थियों को जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा साक्षात्कार के चरण होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के केवल फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से नहीं अंकना चाहिए, बल्कि गंभीरता से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के बीच प्रतियोगिता होती है। इसलिए विद्यार्थियों को अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने अधिकारियों से सविल सर्विसेज की तैयारी, यूपीएससी में सफलता, एनडीए, करियर चयन, हिंदी माध्यम से तैयारी सहित विभिन्न विषयों पर संवाद किया। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने विद्यार्थियों के सवाल का जवाब देते हुए उनका मार्गदर्शन किया और लक्ष्य के प्रति अनुशासन, निरंतर मेहनत तथा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक शतानंद शर्मा, जिला सूचना अधिकारी मो. दाशिश, विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित शिक्षक उपस्थित रहे।

छात्राओं से भरा टेंपो पलटा, तीन छात्राएं घायल, मची अफरा-तफरी

बहजोई/संभल(सब का सपना):- जनपद के बहजोई-चंदौसी रोड पर गांव लहराबन के पास शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब चंदौसी जा रहा एक टेंपो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में टेंपो में सवार तीन छात्राएं घायल हो गईं। गंभीरत रही कि हादसे में किसी छात्रा को गंभीर चोट नहीं आई। जानकारी के अनुसार बहजोई थाना क्षेत्र निवासी आशिक, वंशिका और तृषा, उम्र करीब 17 वर्ष, टेंपो से बहजोई से चंदौसी स्थित एसएम कॉलेज जा रही थीं। तीनों छात्राएं रोजमर्रा की तरह टेंपो में सवार होकर कॉलेज के लिए निकली थीं। बताया जा रहा है कि जैसे ही टेंपो गांव लहराबन के पास



हादसे में क्षतिग्रस्त वाहन

बहजोई-चंदौसी रोड पर पहुंचा, तभी अचानक टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया। टेंपो के पलटते ही उसमें सवार छात्राओं में चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने मौके पर पहुंचकर टेंपो में फंसी छात्राओं को बाहर निकाला और घटना की

सूचना एंबुलेंस को दी। कुछ ही देर में एंबुलेंस मौके पर पहुंची और तीनों घायल छात्राओं को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई ले जाया गया। स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकों ने तीनों छात्राओं का परीक्षण कर उपचार किया।

चिकित्सकों के अनुसार छात्राओं को मामूली चोटें आई थीं और उनकी हालत सामान्य थी। उपचार के बाद तीनों छात्राओं को उनके परिजनों के साथ घर भेज दिया गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद छात्राओं के परिजन भी स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए। परिजनों ने छात्राओं का हालचाल जाना और उन्हें सुरक्षित घर ले गए। हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। हाईवे पर टेंपो पलटने की घटना के बाद कुछ समय के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। हादसा किस कारण से हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

चामुंडा मंदिर की भूमि से हटाया गया अतिक्रमण, बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया अवैध निर्माण

हजरतनगर गढ़ी/सम्भल(सब का सपना):- जनपद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र की नगर पंचायत सिरसी में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चामुंडा मंदिर की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। जानकारी के अनुसार सरकारी अभिलेखों में चामुंडा मंदिर के नाम दर्ज गाटा संख्या 692 की एक बीघा से अधिक भूमि पर कथित रूप से



अवैध कब्जा कर निर्माण कराया गया था। शिकायत एवं अभिलेखीय जांच के बाद प्रशासनिक टीम पुलिस बल

के साथ मौके पर पहुंची और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। प्रशासन की टीम ने बुलडोजर

की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। कार्रवाई के बाद मंदिर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस टीम भी मौजूद रही और कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मचा रहा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण की खेलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

अवैध मिट्टी खनन पर बड़ी कार्रवाई, जेसीबी समेत पांच ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ीं

सम्भल(सब का सपना):- जनपद में अवैध खनन एवं पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के खिलाफ खनन विभाग का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार तड़के करीब दो बजे तहसील सम्भल क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदपुर मालिनी एवं मंगनपुर में मिट्टी खनन की सूचना पर खनन विभाग की टीम ने छापेमारी कर कार्रवाई की। मौके पर जांच के दौरान खनन निरीक्षक शिवम् कुमार ने पाया कि क्षेत्र में मिट्टी का खनन किया जा रहा था। खनन कार्य में पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों एवं निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था।



कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से एक जेसीबी मशीन और पांच ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ लीं। सभी वाहनों को आवश्यक कार्रवाई के लिए थाना हजरतनगर गढ़ी लाया गया। विभाग

द्वारा वाहन स्वामियों के संबंध में जांच की जा रही है। उपलब्ध अभिलेखों एवं जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर खनन एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के तहत

आगे की कार्रवाई की जाएगी। खनन निरीक्षक शिवम् कुमार ने स्पष्ट किया कि जनपद में अवैध खनन अथवा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन कर खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। खनन विभाग ने जनपदवासियों से अपील की है कि कहीं भी अवैध खनन, अवैध परिवहन अथवा खनन संबंधी नियमों का उल्लंघन दिखाई देने पर इसकी सूचना संबंधित प्रशासनिक अथवा विभागीय अधिकारियों को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

भूबरा में राशन घटतौली पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, डीलर पर कार्रवाई की मांग

अंत्योदय कार्ड पर भी 5 किलो कम, दबंगई का आरोप

रहरा/अमरोहा (सब का सपना):- जनपद के विकासखंड गंगेश्वरी के ग्राम भूबरा में सरकारी राशन की दुकान पर घटतौली और मनमानी को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। दर्जनों ग्रामीणों ने एकत्र होकर राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन कर उच्चाधिकारियों से जांच और कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार द्वारा प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं-चावल दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन डीलर द्वारा 4 किलो प्रति यूनिट राशन दिया जा रहा है। यानी हर यूनिट पर 1 किलो राशन की कटौती की जा रही है।



ग्रामीणों ने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो राशन की जगह केवल 30 किलो राशन दिया जा रहा है। पूरा राशन मांगने पर कार्डधारकों को दबंगई और धमकी का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीणों का आरोप है कि जिसके नाम से राशन की दुकान आवंटित है वह महिला गांव में नहीं रहती। वह बाहर रहती है और दुकान का संचालन उसका भतीजा करता है। शिकायत करने पर वह दबंगई

दिखाता है। ग्रामीणों ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राशन कार्ड बनवाने के नाम पर एक व्यक्ति से 2000 रुपये भी लिए गए। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने आपूर्ति विभाग और जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी डीलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस दौरान प्रदर्शन करने वालों में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

पंचायत सहायकों पर गिरी गाज, 24 पंचायत सहायकों को कारण बताओ नोटिस

बहजोई/सम्भल(सब का सपना):- ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की कार्यप्रणाली में लापरवाही को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट की अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में जनपद में कार्यरत पंचायत सहायकों के कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कुछ पंचायत सहायकों के निर्धारित ग्राम पंचायत में निवास न करने, नियमित उपस्थिति दर्ज न कराने तथा पंचायत सचिवालय में अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं करने की बात सामने आई। मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करने वाले 24 पंचायत सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही



संबंधित पंचायत सहायकों को सक्षम स्तर से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। कार्रवाई की जद में विकासखंड बनियाखेड़ा के सात, जुनावई के सात और बहजोई के 10 पंचायत सहायक शामिल हैं। इनमें बनियाखेड़ा ब्लॉक के अनिल कुमार (मौलागढ़), माजिद चौधरी (मौजगंज), धीरेन्द्र कुमार (फरीदपुर खास), मंजू (खेड़ाखास), आकांक्षा (बुद्धनगर खण्डुआ),

सुरभि (रुस्तमगढ़ उगिया) और विनय (भगतपुर मिर्जा) शामिल हैं। इसी प्रकार जुनावई विकासखंड के भावना (अहरोला नवाजी), सुमन कुमारी (दवथरा हिमंचल), बाला (गनुपुरा), ज्योति शर्मा (जलालपुर), उषा यादव (लतीफाधर), पिंकी कुमारी (मईहुसेनपुर खास) और प्रियंका यादव (चिरवारी) को भी नोटिस जारी किया गया है। वहीं बहजोई विकासखंड के सीताराम (बबनेटा), अब्दुल कलाम (विसारू), विकेश (सादातवाड़ी), नीतू (पगौना), हिमांशु शर्मा (नाथौस), अखिलेश (घासीपुर), पुष्पेन्द्र (शेरूआ), संतोष कुमार (अर्जुनपुर जुना), अंजली राघव (मुल्हटा) और पूजा (चौपाशोपापुर) कार्रवाई की जद में आए हैं। मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट ने स्पष्ट किया कि

पंचायत सहायकों का दायित्व ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने तथा पंचायत सचिवालय के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग करना है। निर्धारित ग्राम पंचायत में निवास न करना, नियमित उपस्थिति दर्ज नहीं करना अथवा सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन न करना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने संबंधित खंड विकास अधिकारियों को पंचायत सहायकों की नियमित उपस्थिति और उनके कार्यों का निरंतर अनुश्रवण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही सामने आने पर संबंधित पंचायत सहायकों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जिला विकास अधिकारी को भेंट की गई केनरा बैंक आरसेटी की वार्षिक पत्रिका

बहजोई/संभल(सब का सपना):- केनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी), बहजोई-संभल के निदेशक अनुपम कुमार गुप्ता ने जिला विकास अधिकारी, संभल राम आशीष से शिष्टाचार भेंट कर संस्थान की वार्षिक पत्रिका सप्रेम भेंट की। इस दौरान उन्होंने संस्थान की वर्षभर की प्रमुख उपलब्धियों, स्वरोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विभिन्न विकासवास्तविक गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी। निदेशक अनुपम कुमार गुप्ता ने बताया कि केनरा बैंक आरसेटी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं, महिलाओं एवं इच्छुक उद्यमियों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। संस्थान द्वारा विभिन्न ट्रेडों



में प्रशिक्षण देकर प्रतिभागियों को स्वरोजगार स्थापित करने और आय के स्थायी साधन विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वार्षिक पत्रिका में संस्थान की वर्षभर की उपलब्धियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विभिन्न गतिविधियों तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर सफलतापूर्वक स्वरोजगार स्थापित करने वाले प्रशिक्षुओं की प्रेरणादायक सफलता की कहानियों को प्रमुखता से शामिल

किया गया है। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी राम आशीष ने आरसेटी द्वारा कौशल विकास एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं को हुनरमंद बनाकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में संस्थान का कार्य अत्यंत सराहनीय और उपयोगी है। उन्होंने संस्थान की गतिविधियों को और प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन

की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। शिष्टाचार भेंट के दौरान कौशल विकास, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने, स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा अधिक से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण से जोड़ने को लेकर भी सार्थक चर्चा हुई। अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया। केनरा बैंक आरसेटी द्वारा संचालित प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं को हुनर देकर उन्हें स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

थाना रजबपुर में महिला से छेड़छाड़ के मामले में केस दर्ज, पुलिस ने शुरु की जांच-पड़ताल

रजबपुर/अमरोहा (सब का सपना):- जनपद के थाना रजबपुर क्षेत्र में महिला से छेड़छाड़ के मामले में थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि यह घटना अतरासी पुलिस चौकी से करीब 500 मीटर की दूरी पर हुई थी। बता दें कि इस मामले में पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि घटना 19 अगस्त की शाम करीब 5 बजे की है। गांव निवासी उसका तहरीा देवर जबनर दुकान में घुस आया और छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता का आरोप है कि



आरोपी ने उससे "आई लव यू" कहा और अपशब्दों का प्रयोग किया। विरोध करने पर आरोपी मारपीट पर उतारू हो गया। पीड़िता के अनुसार, विल्लाने की आवाज सुनकर उसके

पति उसे बचाने लड़े, जिसके बाद आरोपी मारपीट करते हुए और जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने यह भी दवा किया है कि आरोपी पर पहले भी

आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसने पूर्व में भी ऐसी हरकतें करने का प्रयास किया था, लेकिन परिवार की इज्जत के चलते पीड़िता ने पहले पुलिस को सूचना नहीं दी थी। पीड़िता ने अतरासी चौकी पर लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने 21 अगस्त, शुक्रवार को प्राप्त तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। रजबपुर थाना प्रभारी विकास सहरावत ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

हिडन कैमरे से अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गैंग का खुलासा

प्रेमजाल में फंसाकर कमरे में बुलाते, वीडियो बनाकर मांगते थे लाखों रुपये, शायी का झांसा देकर भी करते थे वसूली

बहजोई/संभल(सब का सपना):- पुलिस ने हिडन कैमरे से अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने और शायी के नाम पर ठगी कर रकम वसूलने वाले कथित गैंग का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गैंग के सदस्य भोले-भाले लोगों को पहले प्रेमजाल में फंसाकर किराये के कमरे पर बुलाते थे। कमरे में पहले से हिडन कैमरे लगाए जाते थे और अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर बाद में पीड़ितों को वीडियो वायरल करने तथा बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर मोटी रकम मांगी जाती थी। पुलिस अधीक्षक सम्भल कृष्ण कुमार बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि थाना रजपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रमोद उर्फ पालू पुत्र महेन्द्र, वीरेन्द्र उर्फ छोटे पुत्र बालमुकुन्द तथा लक्ष्मी पुत्री महेन्द्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय के समक्ष



पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार को ग्राम देवपुरा निवासी होराम सिंह ने थाना रजपुरा में तहरीर देकर आरोप से फोन पर बात कराकर लोगों को कथित प्रेमजाल में फंसाते थे। इसके बाद उन्हें मिलने के लिए किराये के कमरे पर बुलाया जाता था। पुलिस के अनुसार कमरे में पहले से हिडन कैमरे लगाए जाते थे और वहां की गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाती थी। इसके बाद कथित रूप से वीडियो वायरल करने और बलात्कार के मुकदमे में फंसाने का भय दिखाकर लोगों से रकम वसूली

थाना रजपुरा में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। पृष्ठताल में गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे लोग पहले लक्ष्मी से फोन पर बात कराकर लोगों को कथित प्रेमजाल में फंसाते थे। इसके बाद उन्हें मिलने के लिए किराये के कमरे पर बुलाया जाता था। पुलिस के अनुसार कमरे में पहले से हिडन कैमरे लगाए जाते थे और वहां की गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाती थी। इसके बाद कथित रूप से वीडियो वायरल करने और बलात्कार के मुकदमे में फंसाने का भय दिखाकर लोगों से रकम वसूली

जाती थी। पुलिस का कहना है कि लोकलाज के कारण कई लोग शिकायत नहीं करते थे और आरोपियों को रकम दे देते थे। पृष्ठताल में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि जो लोग प्रेमजाल में नहीं फंसाते थे, उन्हें शायी करने का झांसा दिया जाता था। पुलिस के अनुसार पैसे लेकर लक्ष्मी संबंधित व्यक्ति से शायी कर उसके घर चली जाती थी। उसी रात परिवार के सो जाने के बाद वह कथित रूप से चुपचाप घर से निकलकर वापस आ जाती थी। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को बलात्कार के मुकदमे में फंसाने का डर दिखाकर रुपये वसूल जाते थे। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पृष्ठताल के आधार पर गैंग से जुड़े अन्य लोगों और पूर्व में की गई घटनाओं के संबंध में जानकारी जुटा रही है। मामले में नामजद अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

भाकियू बीआरएसएस की बैठक आयोजित, किसानों के मुद्दों पर बनी रणनीति

संभल(सब का सपना):- भारतीय किसान यूनियन (बीआरएसएस) भारत राष्ट्रीय सेवक संघ द्वारा रविवार को ग्राम - भारतल में जिला महासचिव अनमोल कुमार के नेतृत्व में जनजागरण अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता इस्माइल खां एवं संचालन युवा जिला मीडिया प्रभारी निदेश कुमार ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सम्भल कामेन्द्र चौधरी ने कहा कि किसानों की समस्याएं केवल खेती तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बिजली, गन्ना भुगतान, सरकारी विभागों से जुड़े कार्य, आवागमन पशु और अन्य जनहित के मुद्दों से भी किसान परेशान हैं। संगठन गांव-गांव पहुंचकर किसानों की समस्याओं को चिन्हित करेगा और संबंधित अधिकारियों के समक्ष मजबूती से उठाकर समाधान कराने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि गांव स्तर पर संगठन मजबूत होने से किसानों की सामूहिक आवाज को मजबूती मिलेगी! संगठन द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान चलाकर किसानों को उनके अधिकारों के प्रति



जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव पहुंचकर अधिक से अधिक किसानों को संगठन से जोड़ने का आह्वान किया। बैठक में गन्ना भुगतान, बिजली व्यवस्था, स्मार्ट मीटर, आवागमन पशुओं से फसलों की सुरक्षा, खाद-बीज की उपलब्धता, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र और वारिसनाम दर्ज कराने सहित कई समस्याओं पर चर्चा हुई। ग्रामीणों ने रहस्यमयी बुखार की रोकथाम के लिए गांव में देवा का छिड़काव करने, गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर गांवों के नाम के बोर्ड

लगवाने तथा संभल रेल विस्तार कार्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग भी उठाई। पदाधिकारियों ने कहा कि जनहित से जुड़े सभी मुद्दों को संबंधित विभागों और प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर किसानों के हित में आंदोलन की रणनीति भी तैयार की जाएगी। बैठक के दौरान संगठन विस्तार करते हुए नदीम अली को जिला सचिव (अ. मो.) सम्भल, आजम मलिक को तहसील महासचिव संभल, वसीम मलिक को तहसील महामंत्री, फैजान मलिक

को तहसील प्रभारी, तारीफ अली को तहसील मंत्री, नुरात मलिक को तहसील सचिव, अरशद अली ब्लॉक सचिव नियुक्त किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सम्भल कामेन्द्र चौधरी, जिला संगठन मंत्री चौ. त्रिषपाल सिंह, जिला महासचिव अनमोल कुमार, जिला प्रचार मंत्री सन्तवीर सिंह, जिला महासचिव (अ. मो.) इस्माइल खां, युवा जिला मीडिया प्रभारी निदेश कुमार, जिला मंत्री (अ. मो.) सुफियान पाशा, तहसील संरक्षक सेवक सैनी, तहसील संगठन मंत्री श्रीपाल यादव, तहसील अध्यक्ष (अ. मो.) मेंहदी हसन, ब्लॉक महामंत्री मनीम गुरजर, युवा ब्लॉक उपाध्यक्ष मो. हसन, वरिष्ठ कार्यकर्ता नरेन्द्र चौधरी, मो. दाऊद, अशराफ अली, अजहर हसन, अनवर अली, अमात अली, जाकिर अली, ताहिर अली, भूरे अली, अफसर अली, अकबर अली, अरुण कुमार, आफताब, लवकुश कुमार एवं महिला मोर्चा से ननिहा देवी जिला सचिव, निशा देवी ब्लॉक सचिव, कश्मीरी देवी, दिलवरी बेगम, भूपी देवी आदि सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।

यूजीसी की नई गाइडलाइंस के विरोध में राजपूत संगठनों ने उठाई आवाज

रोलबैक की मांग को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

धामपुर/बिजनौर (सब का सपना):- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से जारी Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026 को लेकर विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। शुक्रवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना एवं राजपूत लेडीज क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों ने धामपुर में प्रदर्शन कर यूजीसी की नई गाइडलाइंस के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नई गाइडलाइंस को तत्काल वापस लेने (रोलबैक) की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने यूजीसी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। संगठनों का कहना है कि नई व्यवस्था को लागू करने से पहले छात्रों, शिक्षकों,



शोधार्थियों और अन्य संबंधित हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श किया जाना चाहिए था। ज्ञापन में संगठनों ने नई नीति के कुछ प्रावधानों को छत्र एवं शिक्षक हितों के प्रतिकूल बताते हुए कहा कि इससे छात्रों की स्वायत्तता, अधिकारों तथा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है। साथ ही शिक्षण संस्थानों पर बढ़ने वाले संभावित वित्तीय एवं प्रशासनिक बोझ को

लेकर भी चिंता जताई गई। संगठनों ने समानता और समावेशिता के संबंध में भी अपनी आशंकाएं व्यक्त कीं। उनका कहना है कि नई व्यवस्था का असर रचित एवं पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक अवसरों पर पड़ सकता है। हालांकि, ये आपत्तियां और आशंकाएं संगठनों की ओर से व्यक्त की गई हैं। ज्ञापन में नीति निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षकों, छात्रों, शिक्षाविदों और अन्य संबंधित पक्षों

के साथ पर्याप्त संवाद नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया। संगठनों ने मांग की कि उच्च शिक्षा से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले से पहले सभी हितधारकों के साथ परदर्शी एवं व्यापक विचार-विमर्श किया जाए। राजपूत संगठनों ने यूजीसी की विवादित गाइडलाइंस को तत्काल वापस लेने, छात्रों एवं शिक्षकों के लोकतांत्रिक अधिकारों तथा अकादमिक स्वतंत्रता की रक्षा करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन किया जाएगा।

ज्ञापन 21 अगस्त को धामपुर में उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। संगठनों के अनुसार, ज्ञापन की एक प्रति केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को भी भेजी गई है।

सिटी पीजी कॉलेज को NIOS से मिली सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी शिक्षा की स्वीकृति

नगीना/बिजनौर (सब का सपना):- सिटी पीजी कॉलेज नगीना का राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS), दिल्ली के माध्यम से सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी स्तर की शिक्षा संचालित करने की मान्यता/स्वीकृति प्राप्त हुई है। कॉलेज प्रबंधन ने इसे शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के नए अवसर खोलने वाली महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार, NIOS दिल्ली तथा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के बीच

हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के अनुपालन में संबंधित NIOS क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सिटी पीजी कॉलेज में विद्यार्थियों को सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी स्तर की शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। कॉलेज के संस्थापक फहीमुद्दीन अंसारी एवं नाजिर अनवर ने बताया कि NIOS के माध्यम से विद्यार्थी सेकेंडरी (कक्षा 10) तथा सीनियर सेकेंडरी (कक्षा 12) स्तर की शिक्षा के लिए प्रवेश ले सकेंगे। सीनियर सेकेंडरी स्तर पर विद्यार्थियों को आर्ट्स,

विज्ञान एवं कॉमर्स स्ट्रीम का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से उन विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा, जो किसी कारणवश नियमित विद्यालयी शिक्षा पूरी नहीं कर सके हैं अथवा अपनी अधूरी शिक्षा को दोबारा जारी रखना चाहते हैं। इससे नगीना और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी शिक्षा के लिए एक बेहतर विकल्प उपलब्ध होगा। संस्थापक फहीमुद्दीन अंसारी एवं नाजिर अनवर ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य क्षेत्र

के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसरों से जोड़ना है। NIOS से मिली स्वीकृति के बाद विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, परीक्षा तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन कॉलेज स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। कॉलेज प्रबंधन ने उम्मीद जताई कि NIOS के माध्यम से संचालित यह शैक्षणिक व्यवस्था नगीना क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी।

नशामुक्त जीवन का संकल्प लेकर विद्यार्थियों ने दिया नशामुक्त भारत का संदेश

नगीना/बिजनौर (सब का सपना):- दस करोड़ नशामुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के अंतर्गत प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवाकेंद्र नगीना की ओर से नगर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। हिंदू इंटर कॉलेज, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज तथा ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रमों में विद्यार्थियों, प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों को नशामुक्त जीवन का सामूहिक संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारी राधा बहन ने प्रधानाचार्य, विद्यालय स्टाफ एवं विद्यार्थियों को हाथ उठाकर नशामुक्त जीवन



अपनाने की प्रतिज्ञा कराई। इस दौरान विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक अभियान में सहभागिता करते हुए नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। ब्रह्माकुमारी राधा बहन ने कहा कि नशामुक्त समाज

ही स्वस्थ, सुखी और सशक्त समाज का आधार है। नशा व्यक्ति के तन, मन, धन और संबंधों को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए युवाओं का नशामुक्त रहना

राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए बेहद आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करते हुए नशामुक्त जीवन अपनाने तथा नशामुक्त भारत के संकल्प से जुड़ने का आह्वान किया। साथ ही विद्यार्थियों की स्वस्थ, सकारात्मक एवं संस्कारयुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने नशामुक्त युवा, नशामुक्त भारत का संदेश देते हुए समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर ब्रह्माकुमारी राधा बहन के साथ बीके नीलम, अलका थापन सहित संबंधित विद्यालयों का स्टाफ मौजूद रहा।

चीनी के दाम बढ़ने से त्योहारों की मिठास होगी फीकी

चीनी के थोक रेट में 15 दिन में हुई 1000 रुपए कुंटल की वृद्धि

नगीना/बिजनौर (सब का सपना):- चीनी के दामों में लगातार हो रही बेतहाशा वृद्धि के कारण रक्षा बंधन व दीवाली के त्योहारों की मिठास फीकी होना प्य है। पिछले 15 दिनों में चीनी के थोक के भाव में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। जबकि फुटकर रेट पिछले ढाई महीने में 17 रुपए किलो बढ़ गए हैं। चीनी के दामों में लगी आग ने महिलाओं की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। मिठाई के रेट भी 340 से 450 रुपए किलो

तक पहुंच गए हैं। बाजार में फुटकर दुकानों पर चीनी 62 रुपए किलो बिक रही है। जबकि गली मोहल्लों की दुकानों पर 65 से 68 रुपए किलो तक चीनी बिक रही है। फुटकर बाजार में चीनी का रेट 4 जून को 45 रुपए किलो, 5 जुलाई को 48 रुपए किलो व 28 जुलाई को 50 रुपए किलो था। अब अचानक 62 से 65 रुपए किलो तक हो गया है। पिछले ढाई महीने में चीनी के फुटकर दाम 17 रुपए किलो तक

बढ़ गए हैं। नगीना में चीनी के सबसे बड़े थोक विक्रेता (मंडी मौलगंज) अमित जैन उर्फ बिककी जैन ने बताया कि आज चीनी का बाजार में थोक का रेट 5930 से 5940 रुपए कुंटल है। पिछले हफ्ते 5300 रुपए कुंटल था। उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों में चीनी के थोक रेट में 1000 रुपए कुंटल तक की वृद्धि हो गई है। नगीना में चीनी की अधिकांश सपलाई द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड बुन्दकी की

है। बुन्दकी शुगर मिल के यूनिट हेड सलिल आर्य से उनकी अवस्थिता के कारण बात नहीं हो पाई। द्वारिकेश शुगर मिल बुंदकी अपने परिसर के स्टोर से भी चीनी के 5 किलो के पोलीबैग की बिक्री करता है लेकिन फिलहाल में उपलब्ध नहीं है। मिल में 5 किलो चीनी का पैक 280 रुपए में किसानों व आम जनता के लिए उपलब्ध होता है।

छह माह की गर्भवती बेटी की मौत पर हत्या का आरोप, एसपी से इंसाफ की गुहार

बिजनौर (सब का सपना):-

जनपद के थाना किरतपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी परिवार ने छह माह की गर्भवती बेटी की मौत के मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मृतका की मां ने बेटी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। परिवार ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। गांव भरैकी निवासी दिनेश सिंह के अनुसार, करीब छह माह पूर्व उनकी बेटी सोनी की शादी किरतपुर थाना क्षेत्र के गांव चंदपुरा निवासी एक युवक के साथ रीति-रिवाज से हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद अतुल नामक युवक ने सोनी को बहला-फुसलाकर



अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसे अपने साथ ले गया। पीड़ित पिता का आरोप है कि इसके बाद सोनी को अतुल और उसके परिजनों द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। परिजनों का आरोप है कि सोनी छह माह की गर्भवती थी। आरोप है कि अतुल और उसके परिवार के लोगों ने

गर्भपात कराने के उद्देश्य से उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों के मुताबिक, इसी दौरान उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना की गई, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो गई। इसके बाद आरोप है कि सोनी की भी हत्या कर दी गई। बेटी की मौत की सूचना मिलने पर परिजन

थाना किरतपुर पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी देकर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित परिवार का आरोप है कि थाने स्तर पर उनकी शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 13 अगस्त को परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मृतका के माता-पिता का कहना है कि बेटी की मौत के बाद से वे न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि नामजद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। परिवार ने एसपी बिजनौर और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है।

महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती को लेकर चलाया गया जनसंपर्क अभियान

चांदपुर/बिजनौर (सब का सपना):-

महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती को भव्य एवं धूमधाम से मनाने को लेकर दक्ष प्रजापति समिति की ओर से नगर चांदपुर सहित आसपास के गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर समाज के लोगों से संपर्क कर जयंती समारोह में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि महाराजा



दक्ष प्रजापति जयंती समाज के लिए गौरव और सम्मान का पर्व है। इसे

सभी लोग आपसी एकता, भाईचारे और उत्साह के साथ मनाएं। उन्होंने

जलभराव बना जानलेवा, बिजली का करंट लगने से दो बैलों की मौत



बिजनौर (सब का सपना):- जलभराव के बीच बिजली का करंट उतरने से दो बैलों की मौत हो गई। हादसे में किसान को करीब 60 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान कराने के साथ पीड़ित किसान को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। बताया गया कि थाना स्योहरा क्षेत्र के गांव



छिल्ला निवासी शोभित पुत्र होशराम शुक्रवार को बैल-बुग्गी लेकर चकमेंहदूद सानी से होते हुए अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान फाटक के पास सड़क पर काफी पानी भरा हुआ था। पानी से होकर बैल-बुग्गी निकालते समय अचानक उसमें बिजली का करंट प्रवाहित हो गया। करंट की चपेट में आने से दोनों बैलों की मौके पर ही मौत हो गई। किसान के अनुसार मृत बैलों की कीमत

करीब 60 हजार रुपये थी। हादसे के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। ग्राम प्रधान मोहम्मद कासिम ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही विद्युत विभाग को सूचना देकर बिजली आपूर्ति बंद कराई गई। संबंधित अधिकारियों को भी घटना से अवगत कराया गया है। स्थानीय निवासी साजिद ने कहा कि लंबे समय से जलभराव के

चौपाल कार्यक्रम में डीडीओ ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

बिजनौर (सब का सपना):-

जनपद बिजनौर के मोहम्मदपुर देवमल में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जिला विकास अधिकारी रचना गुप्ता ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए उनके शीघ्र निराकरण किये जाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर नसरीन अमित व सुधा ने राशन नहीं मिलने की शिकायत की, आसमीन



पत्नी फुरकान राशन कार्ड में यूनिट

नहीं बढ़ने तथा मनरेगा में काम नहीं

सड़क हादसे में घायल युवक की मौत, नहटौर मार्ग पर अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर

बिजनौर (सब का सपना):-

जनपद बिजनौर के नहटौर-कोतवाली देहात मार्ग पर हुए एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 26 वर्षीय युवक कुलदीप कुमार की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह घटना ग्राम फुलमंदा (फुलसंदा) के पास हुई थी। जानकारी के अनुसार, ग्राम करीमपुर निवासी सोनोनराम सिंह के पुत्र कुलदीप कुमार हरिद्वार में नौकरी करते थे। वह अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। नहटौर-कोतवाली देहात मार्ग पर ग्राम फुलमंदा के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कुलदीप कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए।



हादसे के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल नहटौर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुलदीप की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें पहले जिला अस्पताल रेफर किया। बाद

में बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर जौली ग्रांट अस्पताल भेजा गया, जहाँ उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।

हल्का दरोगा संयम यादव ने बताया कि अज्ञात वाहन और उसके चालक का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

रोजगार तलाशने के बजाय युवा शुरू करें अपना स्टार्टअप:- नदीम



शिकारपुर/बुलंदशहर (सब का सपना):- श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय में विश्व उद्यमिता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को रोजगार तलाशने के बजाय स्वयं का स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आईपी प्रोफेशनल नदीम ने कहा कि उद्यमिता नए विचारों, नवाचार और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम है। इंस्टीटयूशनल इनोवेशनल सेल के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों को बौद्धिक संपदा अधिकारों की जानकारी दी गई। साथ ही युवाओं से स्वयं रोजगार पाने के साथ अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर विषय आधारित वि्वज प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का संयोजन डीन एकेडमिक्स डॉ. अमित पाराशर एवं रुचि राघव ने किया। प्राचार्य डॉ. ललित गुप्ता, नैक कोऑर्डिनेटर रेशु भारद्वाज सहित महाविद्यालय के शिक्षक एवं छात्र मौजूद रहे। संचालन लशिका, इशू पलावत एवं श्रेया ने संयुक्त रूप से किया।

ई-लाटरी के माध्यम से कृषियंत्रों के वितरण के लिए कृषकों का किया गया चयन

फतेहपुर (सब का सपना):- कृषि यंत्रोंकरण योजना के अन्तर्गत शुक्रवार को विकास भवन में ई-लाटरी के माध्यम से कृषकों का चयन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना एवं प्रमोशन आफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेजीड्यू (सीआरएम) योजनान्तर्गत वर्ष 2026-27 में अनुदान पर यन्त्र क्रय करने के लिए 16 जुलाई से 10 अगस्त के मध्य कृषि विभाग के पार्टल पर आनलाइन बुकिंग करने वाले कृषकों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से विकास भवन सभागार में किया गया। उप निदेशक कृषि ने बताया कि इन-सीटू एवं एसएमएसएम योजनान्तर्गत विभिन्न प्रकार कृषि यंत्रों के लक्ष्य के सापेक्ष 743 किसानों ने विभिन्न प्रकार के कृषि



यंत्रों की बुकिंग की गई जिसके सापेक्ष जनपद स्तर पर 109 किसानों का ई-लॉटरी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के लाभार्थियों का चयन किया गया। जिसमें 11 कस्टम हायरिंग सेंटर (परियोजना लागत रू0 10.00 लाख), 12 रोटावेटर, 08 लेजर लैण्ड लवेलर, 02 कम्बाइन हार्वेस्टर, 02 ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर, 02 स्ट्रॉपर, 05 पावर आपरेटड चैफ कटर, 03 मल्टीक्राफ थ्रेसर, 02 मिनी राइस मिल, 02 कल्टीवेटर, 02 हैरो, 02

इसके अतिरिक्त कृषि निदेशालय द्वारा लक्ष्य के बराबर बुकिंग होने के कारण विभिन्न प्रकार के 40 किसानों का स्वतः चयन किया गया है। उप कृषि निदेशक ने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि कृषि विभाग द्वारा चयनित कृषकों को कृषि यंत्र मानक के अनुरूप नियमानुसार पंजीकृत फर्म से खरीद कर अतिशीघ्र निर्धारित समय सीमा के अन्दर कृषि विभाग के पार्टल पर बिल अपलोड कर दें। जिससे अतिशीघ्र सत्यापन के बाद अनुदान की धनराशि प्रेषित की जा सके। इस दौरान ई-लाटरी समिति के सदस्य उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, एल०डी०एम०, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, प्रगतिशील कृषक, सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रतिनिधि सहित विभिन्न विकासखण्डों के यंत्र बुकिंग करने वाले लगभग 150 किसान उपस्थित रहे।

पावर टिलर, 02 किसान ड्रोन, 02 डी०एस०आर०, 02 आलू खुदाई मशीन, 02 आलू बुवाई मशीन, 01 ऑयलमिल विद फिल्टर प्रेस, 01 ट्रैक्टर आपरेटड कम्बाइन हार्वेस्टर, 36 सुपर सीडर, 04 कस्टम हायरिंग सेंटर (परियोजना लागत रुपये 30.00 लाख), 02 पैडी स्ट्रॉ चॉपर, 01 हे-रेक, 01 पावर वीडर, 01 रिवर्सिबुल एम०बी०क्लाउ एवं 01 क्राप रीपर ट्रैक्टर माउन्टेड के लिए जनपद के विभिन्न विकास खण्डों के कृषकों का चयन किया गया।

टैंकर में मिला मिलावटी दूध, 1.20 लाख का दूध नष्ट



मथुरा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को राया रेलवे फाटक पर कार्रवाई करते हुए 2000 लीटर दूध से भरे टैंकर को पकड़ा। त्वरित जांच में दूध में स्टार्च की मौजूदगी और फैट की मात्रा कम पाए जाने पर खाद्य विभाग ने दूध का नमूना लेकर जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेजा। वहीं, शेष करीब 1.20 लाख रुपये कीमत के दूध को जनहित में मौके पर नष्ट करा दिया गया। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा जिलाधिकारी मथुरा के आदेश के अनुपालन में सहायक आयुक्त (खाद्य) डॉ. जतिन कुमार सिंह के निर्देशन एवं नेतृत्व में खाद्य सचलदल ने राया रेलवे फाटक पर दूध टैंकर संख्या यूपी 86 एटी 0875 का निरीक्षण किया। टैंकर चालक हेमनेस कुमार ने टीम को बताया कि उसमें करीब 2000 लीटर दूध गोपाल डेयरी, सिकंदराराऊ (हाथरस) से लाया गया है। निरीक्षण के दौरान चालक दूध के क्रय-विक्रय से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। दूध की गुणवत्ता पर संदेह होने पर राया स्थित डेयरी पर टैंकर में भरे दूध की त्वरित जांच की गई। जांच में दूध में स्टार्च मिलने के साथ ही फैट की मात्रा कम पाई गई। इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दूध का नमूना संग्रहित कर राजकीय खाद्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया। शेष दूध को जनहित में तत्काल नष्ट करा दिया गया। नष्ट किए गए दूध की अनुमानित कीमत करीब 1.20 लाख रुपये बताई गई है। खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित के खिलाफ नियमानुसार अग्रत कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे।

डिडौली क्षेत्र में 4 दिन से लापता 3 साल की बच्ची का शव तालाब में मिला, पुलिस कर रही जांच-पड़ताल



डिडौली/अमरौहा (सब का सपना):- जनपद के थाना डिडौली क्षेत्र में लापता हुई एक 3 साल की बच्ची का शव शुक्रवार को चौथे दिन पुलिस ने एक तालाब से बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बच्ची की मौत का कारण साफ हो सकेगा। फिलहाल पुलिस इस मामले में गहनता से जांच पड़ताल में जुटी है। बता दें कि पूरा मामला थाना डिडौली क्षेत्र के ढकिया चमन गांव का है जहां चार दिन से लापता तीन वर्षीय बच्ची अमायरा का शव शुक्रवार

सुबह तालाब से बरामद हुआ। बच्ची के अचानक लापता होने के बाद से परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई थी और बच्ची की तलाश की जा रही थी। शुक्रवार की सुबह गांव के ही तालाब में शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कण मच गया बताया गया कि अमायरा चार दिन पहले अचानक घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने आसपास के इलाकों में काफी तलाश की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने भी बच्ची की तलाश शुरू की और उसके लापता होने से जुड़े सभी



संभावित स्थानों पर जानकारी जुटाई। शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे गांव के एक तालाब में बच्ची का शव दिखाई दिया। सूचना मिलते ही डिडौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल बच्ची की मौत कैसे हुई, यह स्पष्ट नहीं है। पुलिस लापता होने से लेकर शव मिलने तक की पूरी घटना की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बच्ची की मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस फिलहाल सभी संभावनाओं को ध्यान में

रखकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बच्ची के लापता होने और तालाब में शव मिलने के बीच की परिस्थितियों को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस गांव और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। बच्ची के लापता होने के समय उसके आसपास कौन-कौन लोग थे, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नूडल्स खाने से परिवार के छह सदस्य बीमार, जांच को भेजा गया नमूना

सम्भल(सब का सपना):- जनपद के ग्राम गुमसानी में नूडल्स खाने के बाद एक ही परिवार के छह सदस्यों की तबीयत खराब होने की शिकायत सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पीड़ित परिवार से जानकारी लेने के साथ ही संबंधित किराना दुकान का निरीक्षण कर नूडल्स का नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। दैनिक समाचार पत्रों में नूडल्स खाने से स्वास्थ्य खराब होने की खबर प्रकाशित होने

के बाद शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजीव कुमार करीब 9:50 बजे ग्राम गुमसानी पहुंचे। उन्होंने ज्ञान सिंह पुत्र पुरन सिंह के घर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। ज्ञान सिंह ने बताया कि उनकी बेटी ने पड़ोस स्थित सुरेन्द्र की दुकान से चार पैकेट नूडल्स खरीदे थे। प्रत्येक पैकेट 22 ग्राम का बताया गया है। परिवार के अनुसार नूडल्स खाने के करीब 30 मिनट बाद परिवार के छह सदस्यों की तबीयत खराब होने की शिकायत हुई। परिजनों ने घर पर मौसमी का जूस



और ओआरएस का सेवन कराया। इसके बाद परिवार के सदस्यों का गुमसानी स्थित निजी अस्पताल में

उपचार कराया गया। वर्तमान में सभी की हालत ठीक बताई गई है। मामले की जानकारी के बाद खाद्य सुरक्षा

अधिकारी राजीव कुमार ने गुमसानी स्थित सुरेन्द्र सिंह किराना,जनरल स्टोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारकर्ता सुरेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह द्वारा खाद्य कारोबार से संबंधित पंजीकरण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। दुकान में मानव उपभोग एवं सार्वजनिक बिक्री के लिए रखे गए उसी बैच के नूडल्स का नमूना खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने संग्रहित किया। नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही नूडल्स की गुणवत्ता और स्वास्थ्य खराब

होने के कारणों के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। खाद्य विभाग के अनुसार निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाने पर दुकान को पूर्णतः बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित कारोबारी को खाद्य पंजीकरण प्राप्त करने के बाद ही खाद्य कारोबार संचालित करने के लिए निर्देशित किया गया है। खाद्य विभाग की कार्रवाई के बाद अब प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

त्योहार से पहले महंगाई का तड़का, चीनी के दाम आसमान पर



बुलंदशहर (सब का सपना):- रक्षाबंधन और जन्माष्टमी से पहले बाजार में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पहासू में दुकानदारों के अनुसार चीनी के दाम महज आठ दिनों में करीब 42 रुपये से बढ़कर 65 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा रिफाईंड और सरसों तेल के दाम भी करीब 200 रुपये किलो बताए जा रहे हैं। मसालों की कीमतों में भी तेजी से लोगों का घरेलू बजट प्रभावित हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि महंगे दाम पर खरीदे गए सामान के कारण उन्हें भी नुकसान का डर है। वहीं मिठाई कारोबारियों के अनुसार चीनी महंगी होने से मिठाइयों की लागत बढ़ सकती है। आम लोगों ने बढ़ती महंगाई पर चिंता जताते हुए कहा कि त्योहार मनाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है।

बरई खुर्दे गाँव में सहकारी समिति का पूर्व विधायक ने फीता काट कर किया उद्घाटन



पूर्व विधायक ने कहाकि भाजपा की सरकार में सबका साथ सबका विकास की भावना से कार्य करना आज ग्रामीणों को मजबूत कर रही है। भाजपा सरकार में सभी लोगों को उनके पास के क्षेत्र में ही सभी सुविधा पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। गरीबों व वंचितों को सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाएँ बनायीं है जो आज उनको लाभ प्रदान कर रही है। कार्यक्रम में उपस्थित अभिषेक

प्रताप सिंह अध्यक्ष बिल्दा कॉर्पोरेट ने विक्रम सिंह पूर्व विधायक के अथक प्रयासों से यह समिति की स्थापना की गई है। पूरे क्षेत्रवासियों आपके आजीवन आभारी रहेंगे। कि आपने सबके साथ किसानों के बारे में चिन्ता करके यह समिति की स्थापना कराई। वही उपस्थित सैकड़ों किसानों ने विक्रम सिंह का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

उद्घाटन समारोह में सचिव आशीष प्रताप सिंह, अभिषेक प्रताप सिंह अध्यक्ष बिलंदा कॉर्पोरेट, आशीष लोधी, ग्राम प्रधान सन्तलाल पाल , सुधांशु पाण्डेय मण्डल अध्यक्ष, सुनील पासवान, अंकित मिश्रा कॉर्पोरेट, अंगद पाल, रमेश पाल, रईस अहमद, ओम प्रकाश लोधी, डॉ अर्जुन लोधी, राधे लोधी, विजय लोधी समेत सैकड़ों क्षेत्रीय किसान मौजूद रहे।



अद्वैतिक-सभा के ब्रेकअप की खबरों ने पकड़ा जोर

अभिनेता ऋतिक रोशन कई साल से सबा आजाद को डेट कर रहे हैं। दोनों को अक्सर साथ में पार्टी और इवेंट में देखा जाता है। सोशल मीडिया पर भी दोनों एक-दूसरे पर खूब प्यार लुटाते हैं। मगर, इन दिनों बी-टाउन में दोनों के ब्रेकअप की अटकलों ने जोर पकड़ा है। इसकी वजह ऋतिक रोशन की प्रोफाइल का कथित तौर पर एक डेटिंग एप पर डेला जाना है।

सुजैन खान से तलाक के बाद ऋतिक रोशन की जिंदगी में सबा आजाद की एंट्री हुई है। दोनों के बीच उम्र का काफी अंतर है। मगर, आपसी समझ काफी अच्छी है। अक्सर दोनों

छुट्टियां मनाने जाते हैं। साथ में पार्टी करते हैं और बॉलीवुड के कई इवेंट्स में साथ में शिरकत करते हैं। मगर, इन दिनों ऐसी अफवाहें हैं कि दोनों की राहें जुदा हो गई हैं।

क्यों शुरू हुई अटकलें

सबसे से ऋतिक के रिश्ते में दूरी की वजह, एक डेटिंग एप पर अभिनेता की प्रोफाइल का पाया जाना है। दरअसल, 'साया' नाम के एक डेटिंग एप पर ऋतिक रोशन की प्रोफाइल होने का दावा किया गया है। इसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल स्क्रीनशॉट में ऋतिक के प्रोफाइल बायो में

‘एक्टर/ प्रोड्यूसर/ एंटरप्रेन्योर’ लिखा दिख रहा है। इस वायरल प्रोफाइल के बाद ही ऐसे सवाल आ रहे हैं कि क्या दोनों का ब्रेकअप हो गया है? हालांकि, रिलेशनशिप को लेकर चल रही अटकलों पर अभी तक ऋतिक रोशन और सबा आजाद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।



रुक्मिणी वसंत ने टॉक्सिक
को बताया अब तक किए हर
काम से बिल्कुल अलग

मुंबई में टॉक्सिक : अ फेयरी टेल फॉर ग्रीन-
अप्स के म्यूजिक लॉन्च पर रुक्मिणी वसंत ने
फिल्म का हिस्सा बनने और मेलिसा की दुनिया
में कदम रखने के अपने एक्सपीरियंस के बारे
में बात की। उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट
उनके अब तक के किए गए काम से बिल्कुल
अलग है।

टॉक्सिक को अपने लिए खास बताते हुए रुक्मिणी ने कहा, टॉक्सिक मेरे लिए, और इस फिल्म का हिस्सा रहे हर इंसान के लिए बेहद स्पेशल फिल्म है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में मैं जान कर राखी दूँ।

बार में न बता कर फिरोज़ का हाथ
 जिस दुनिया में हम रहते हैं,
 उसका एकसर्पेसाथ होना, फिम्म का
 स्केल... पहली बार जब मैंने
 इसके बारे में सुना था, तभी
 इसका स्केल मुझे बहुत इम्प्रेस
 कर गया था। हालांकि, रुविम्वी
 ने बताया कि उन्हें फिम्म की
 तरफ सिर्फ इसका स्केल और
 ग्रैंडयोर की नहीं खींच लाया,
 बल्कि इसके किन्दरारों की
 कॉम्प्लेक्सिटी ने भी उन्हें काफी
 एक्साइट किया। उन्होंने कहा,
 फिम्म के स्केल और इस दुनिया
 की ग्रैंडयोर के साथ-साथ, हर
 किन्दरार को ये शोध भी बहुत
 शानदार है। हर किन्दरार इतना रॉ
 और इतना ह्यूमन है।

रुविमणी ने बताया कि वह यह जानने को लेकर काफी एक्साइटेट थी कि टॉक्सिक थी। इस बड़ी दुनिया में मेलिसा की जगह क्या है और उसका बाकी किरदारों के साथ कनेक्शन कैसा है। उन्होंने कहा, मैं यह डिस्कवर करने को लेकर बहुत एक्साइटेट थी कि मेलिसा इस दुनिया में कहाँ फिट होती है और बाकी किरदार एक-दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। यह सब किताब तरह आपस में जुड़ा हुआ है, इसे लेकर मैं बहुत थिरक रही थी। एक्टर ने यह भी माना कि यश के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलना उनके लिए एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। रुविमणी ने कहा, यश सर की फैनगल होना और फिर उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलना, मेरे लिए यह भी एक बहुत शानदार एक्सपीरियंस था। जब रुविमणी से पूछा गया कि टॉक्सिक को उनके लिए इतना खास क्या बनाता है, खासकर तब जब अंडीयंस ने उन्हें इससे पहले ऐसी दुनिया या किरदार में नहीं देखा है, तो उन्होंने कहा, यह अब तक मैंने जो भी काम किया है, उससे निराला अलग है। मुझे लगता है कि इसमें एक यूनिक्स है और उनके किरदार में एक खास तरह का जे ने से स्वा है। गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी टॉक्सिक। अ फेस्टी टेल फॉर ग्रोन-अप्स में यश, मयनतारा, कियारा आवाणी, तारा सुतारिया, रुविमणी वस्तंत और हुमा कुरेशी नजर आएंगे। फिल्ट 26 अगस्त 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।



**वीर पहाड़िया को
बिल्कुल अलग
अंदाज में पेश करेगी
'प्रेम कीटाणु'**

रकार्ड फोर्स से बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद वीर पहाड़िया लगातार बॉलीवुड में अपना सबकुछ कायम करते जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा महेश भट्ट की नाम - टू लिव इज वॉर के बाद उनकी अगली सिप्टिकल फिल्म प्रेम कीटाणु, जिसकी घोषणा उन्होंने हाल ही में की है। इस फिल्म में वीर पहाड़िया के साथ अपारशक्ति खुराना, आफिया सैयद, राकेश बेदी और निखिल विजय भी नजर आएंगे।

‘प्रेम कीटाणु’ का निर्देशन अपूर्व सिंह कार्की ने किया है, जो ‘सिर्फ एक बंदा काफी है’ और वॉल्ट डिज़नी की ‘एप्सिरेट्स’ के लिए जाने जाते हैं। यह फिल्म गौरव वर्मा के ले-ऑन फिल्म गैंग बैंडर अलिका फिल्म की पहली प्रोडक्शन है, जिसने फार्स फिल्म के साथ मिलकर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसकी कहानी युवाओं की आकांक्षाओं, रिश्तों और रोजमर्रा की चुनौतियों के इर्द-गिर्द घूमती इस फिल्म की कहानी एक दिल छू लेने वाली और लिटेरेबल एट्टरनेन है। हास्य और भवनाओं से भरपूर इस फिल्म में आधुनिक जीवन और प्यार को एक नए नजरिए से पेश करने की कोशिश भी की गई है। ऐसे में यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ‘प्रेम कीटाणु’ वीर पहाड़िया को उनके डेब्यू ‘स्काई फोर्स’ से बिस्कुल अलग अंदाज में पेश करेगी। ‘स्काई फोर्स’ में उन्होंने भारतीय वायुसेना के अधिकारी टी. विजया का किरदार निभाया था। वीर अपने करियर के शुरुआती दौर में ही अलग-अलग तरह के किरदार और जानेंत लताश रहे हैं। तैसा कि वीर की आगामी फिल्मों की लिस्ट में डाकै एक्शन थ्रिलर ‘नाम – टू लिट इज वीर’ भी शामिल है।

महेश भट्ट द्वारा प्रस्तुत और सिद्धांत सचदेव द्वारा निर्देशित इस फिल्म में दो के साथ वरुण शर्मा नजर आयेगें, जो पहली बार नेगेटिव भूमिका में दिखाई देने की उम्मीद है। फिल्म का निर्माण रविंद्र चावड़ा और उत्सव उपाध्याय कर रहे हैं। 'प्रेम कीटाणु' और 'नाम - दू लिज इज वॉर' के जरिए वीर पहाड़िया दो बिब्लूक अलग सिनेमाई दुनिया का हिस्सा बन रहे हैं। एक और जहां 'प्रेम कीटाणु' रोमांस, हास्य और युवा भावना के रोजमर्रा की वास्तविकताओं को समेटने लागी, वहीं 'नाम - दू लिज इज वॉर' में उनका एक ड्रैट्स और रजद एक्शन अवतार देखने को मिलेगा। 'स्काई फोर्स' के बाद इन दोनों फिल्मों की घोषणा वीर पहाड़िया के करियर के अगले चरण की ओर इशारा करीती है, जहां अभिनेता किसी एक इमेज तक सीमित रहने के बजाय अलग-अलग जॉर्न और किरदारों के जरिए अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं।



आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म 'प्रलय' में नजर आएंगी कल्याणी प्रियदर्शनी, रणवीर सिंह ने शुरू की शूटिंग

रणवीर सिंह ने अपनी आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म 'प्रलय' की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म में लीड रोल निभाने के साथ ही रणवीर इस फिल्म से बतौर निर्माता भी जुड़े हैं। 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' की सफलता के बाद रणवीर सिंह का यह पहला प्रोजेक्ट है। इस फिल्म को लेकर अभिनेता के फैंस बेहद एक्साइटेड हैं।

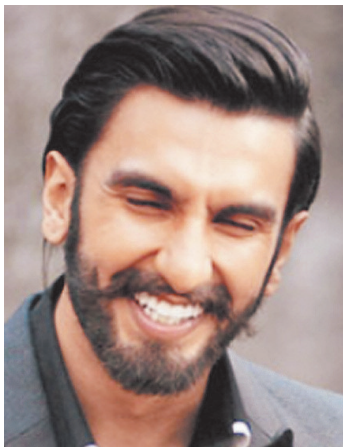
‘प्रलय’ को रणवीर के करियर का सबसे बड़े प्रोजेक्टवस बताया जा रहा है। फिल्म की शूटिंग मुंबई में शुरू हो चुकी है। इसे लाइव लोकेशन पर भी शूट किया जाएगा। रणवीर इस फिल्म में अभिनय करने के साथ ही इसका निर्माण भी कर रहे हैं। यह एक धमाकेदार एक्शन फिल्म होगी। रणवीर के लिए यह महत्वकांक्षी प्रोजेक्टवस में से एक है। फिल्म में ‘लोका’ फेम एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शनी भी अभिनय करती नजर आएंगी।

बड़े पैमाने पर होगा काम

रिपोर्टर्स के मुताबिक 'प्रलय' की कहानी काफी हद तक विजुअल एक्टिविटी पर निर्भर करेगी। फिल्म में धुआंधार एक्शन सीन्स भी होंगे। रणवीर इस फिल्म के डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान क्रिप्टिव चर्चाओं में भी एक्टिव रूप से शामिल हुए हैं। लगभग 300 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली 'प्रलय' रणवीर सिंह के करियर की सबसे महंगी स्टैंडअलोन फिल्म हो सकती है।

फिल्म 'प्रलय' के बारे में

‘प्रलय’ में रणवीर सिंह मुख्य
किरादार में नजर आएंगे।
वहीं कल्याणी प्रियदर्शन भी
अहम भूमिका निभाएंगी।
फिल्म का निर्देशन
जय मेहता कर रहे
हैं। वहीं फिल्म
का निर्माण
अनन्या
बिड़ला
स्टूडियोज
कर रहा
है।



‘7 डॉग्स’ की रिलीज को लेकर बेहद उत्साहित हूं

अभिनेता संजय दत्त जल्द ही सलमान खान के साथ इंटरनेशनल फिल्म '7 डॉग्स' में नजर आएंगे। यह फिल्म अगले हफ्ते रिलीज होने वाली है। एक्टर ने इस फिल्म में काम करने के अपने अनुभव को साझा किया।

फिल्म '7 डॉग्स' एक अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। कुछ दिन पहले ही मेकर्स ने फिल्म का नया ट्रेलर लॉन्च किया था। अब इस फिल्म के बारे में संजू बाबा ने अपने अनुभव बताए। संजू ने कहा मैं '7 डॉग्स' के दर्शकों तक पहुंचने को

लेकर बेहद उत्साहित हूँ। मुझे भारत में इसके रिलीज होने का बहुत इंतजार था। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट में अंतरराष्ट्रीय टीम के साथ काम करने का काफी खास अनुभव रहा है। इस तरह के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका जिंदगी में बार-बार नहीं मिलता। यह फिल्म देखकर खुबि दार्शिकों को पसंद आएगी। उन्हें इसे प्लेक्स खरीब मजा आने वाला है। जब दार्शिक इसे बड़े पर्दे पर देखेंगे तो उनके लिए यह अलग तरह का अनुभव होगा। अपनी बातचीत में आगे संजय दत्त ने कहा, 'मुझे लगता है भारतीय दर्शकों को इस फिल्म को खूले मन से देखना चाहिए और वे हैरान रह

जाएंगे। यह एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म है, लेकिन इसकी भावनाएं दर्शकों के लिए आसानी से जुड़ने वाली हैं। इसमें एक्शन है, ड्रामा है, दमदार किरदार हैं और फिल्म को बहुत बड़े स्तर पर बनाया गया है।'



रानी मुखर्जी को मेलबर्न में मिला खास सम्मान

राजी मुखर्जी ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक अलग-अलग किस्मों का निभाया है। उन्होंने कभी सामान की सौच को चुनौती देने वाली महिलाओं का किरदार निभाया, तो कभी मुश्किल हालात में हिम्मत दिखाने वाली महिलाओं की कहानी पर पड़ उतरी। अब इसी को देखते हुए उन्हें विशेष सम्मान दिया गया है। तीन दशक से ज्यादा समय से अपनी थानदार पेंटिंग से दर्शकों का दिल जीतने वाली राजी को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेनलबन में खास सम्मान दिया गया है।

उन्हें एक्टिंग में बेहतरीन योगदान के लिए स्पेशल सिटेशन से सम्मानित किया गया। रानी के इस सम्मान को भारतीय सिनेमा में उनके लंबे और

शानदार साफ़र के लिए एक बड़ी पहचान कायम जा रहा है। उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे किरदार निभाए हैं, जिन्हें आज भी दर्शक याद करते हैं। उनके किरदारों और फिल्मों ने भारत के साथ-साथ विदेशों में भी लोगों के दिलों तक जगह बनाई है। 'लूक', 'हम तुम', 'युवा', 'बटी और बबली', 'नो वन किल जैसिका', 'हिक्की', 'मदानी' फ़्रेञ्चाइजी और 'मिसेज वटजी वरसंज नॉव' जैसी फिल्मों में रानी की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया है। रानी ने हर फिल्म में अपने किरदार को पूरी ईमानदारी और भावनाओं के साथ निभाने की कोशिश की है। यही वजह है कि उनके कई किरदार आज भी दर्शकों के बीच खास जगह रखते हैं।

इस सम्मान के बाद रानी मुखर्जी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी फिल्मों, उनके किरदार और उनकी आवाज घर से बहुत दूर तक पहुंची हैं। उनके लिए यह सफ़र बहुत खास रहा है। रानी का यह सम्मान रिफ़्ट उनकी एक्टिंग को पहचान नहीं देता, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारतीय सिनेमा की कहानियाँ अब दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में दर्शकों तक पहुंच रही हैं।